मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/05256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

| वर्ष : 27 | अंक : 02 |

| अक्टूबर 2026 |



क्या है E20, कंपनियां और 1.72 लाख करोड़ की सरकारी खरीद का पूरा कनेक्शन?

एथेनॉल को लेकर देश में मचा हाहाकार: सवाल ईंधन का ही नहीं, भरोसे का भी

एथेनॉल की अर्थव्यवस्था में गडकरी परिवार



प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक विजया पाठक
कार्यकारी संपादक समता पाठक
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय
भोपाल
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़
4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक
विजया पाठक द्वारा जगत प्रिंटर्स पब्लिशर्स, खसरा नं. 1/1/6 अमरावद खुर्द बरखेड़ा पठानी, फंदा भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.co.in



(पृष्ठ क्र.-6)

- विष्णुदेव साय सरकार में युवाओं को रोजगार और उद्योग के क्षेत्र में नए अवसरों का विस्तार 29
- मध्यप्रदेश में जहरीली शराब से मौत 34
- ब्रिक्स सम्मेलन एक लेखा-जोखा 44
- मनुष्य बनने की ओर कृत्रिम बुद्धि रोबोट 48
- हनुमान अंश की टीम की अनोखी कहानी 51
- दमोह जिले में क्रांति का मोर्चा थामा हिंडोरिया के किशोर सिंह 56
- पेट्रोल-डीजल के बढ़ते खर्च के बीच सरकार का बड़ा कदम ! 59
- 80 years after Independence, we, the manual scavengers, are still fighting for our freedom.....61


कहीं हम पर भी न लग जाए...
CBI
विजया

ट्रंप-जिनपिंग वार्ता : संवाद से संबंधों में स्थिरता की उम्मीद

विश्व राजनीति में अमेरिका और चीन के संबंधों का महत्व किसी एक द्विपक्षीय रिश्ते तक सीमित नहीं है। दुनिया की दो बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्तियों के बीच संबंधों का असर वैश्विक व्यापार, तकनीक, निवेश, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर पड़ता है। ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वाशिंगटन में हुई वार्ता को इस व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने मुलाकात को सकारात्मक बताया और संबंधों में रणनीतिक स्थिरता तथा सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। इस वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि दोनों देशों ने संवाद का रास्ता खुला रखा है। पिछले कुछ वर्षों में व्यापार शुल्क, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, दुर्लभ खनिजों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों ने अमेरिका-चीन संबंधों में तनाव बढ़ाया है। ऐसे माहौल में शीर्ष नेतृत्व के बीच सीधा संवाद गलतफहमियों को नियंत्रित करने और विवादों को प्रबंधित करने का माध्यम बन सकता है। चीन की ओर से दोनों देशों के बीच सम्मान, निष्पक्षता और पारस्परिकता पर आधारित रणनीतिक स्थिरता की बात कही गई है। अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक संबंध इस वार्ता का महत्वपूर्ण आधार हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए पहले से चल रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने पर ध्यान रहा। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार व्यापार युद्ध पर रोक से जुड़े मौजूदा समझौते को जनवरी तक बढ़ाने पर सहमति बनी है, हालांकि व्यापक व्यापार समझौते के लिए बातचीत अभी जारी रहनी है। इसका अर्थ यह है कि तत्काल टकराव को टालने की कोशिश तो हुई है, लेकिन दीर्घकालिक आर्थिक मतभेद समाप्त नहीं हुए हैं। शुल्क, बाजार पहुंच, औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला और रणनीतिक तकनीकों से जुड़े प्रश्न आगे भी दोनों देशों के लिए चुनौती बने रहेंगे।

एआई अब अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा का एक प्रमुख क्षेत्र बन चुका है। दोनों देशों के लिए यह तकनीकी विकास के साथ-साथ आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी है। वार्ता में एआई से जुड़े जोखिमों और सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई, लेकिन किसी बड़े समझौते की घोषणा नहीं हुई। यह स्थिति बताती है कि तकनीकी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों साथ-साथ चलेंगे। एआई जैसी तकनीक के साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को देखते हुए दोनों देशों के बीच संवाद बनाए रखना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के हित में भी है।

ताइवान, ईरान और अन्य क्षेत्रीय मुद्दे भी अमेरिका-चीन संबंधों को प्रभावित करते हैं। इन विषयों पर दोनों देशों के हित और दृष्टिकोण अलग हैं। इसलिए केवल शीर्ष नेतृत्व की एक बैठक से इन मतभेदों का समाधान संभव नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि संवेदनशील मुद्दों पर संवाद के नियमित माध्यम बने रहें और प्रतिस्पर्धा को अनियंत्रित टकराव में बदलने से रोका जाए। हालिया वार्ता में भी कुछ प्रमुख मुद्दों पर ठोस सफलता सीमित रही। अमेरिका और चीन के बीच स्थिर संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय तक तनाव रहने से व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर पड़ सकता है। इसके विपरीत, संवाद और सीमित क्षेत्रों में सहयोग से वैश्विक बाजारों को अधिक स्थिर वातावरण मिल सकता है। इसलिए ट्रंप-जिनपिंग वार्ता का महत्व किसी एक समझौते से अधिक संवाद की निरंतरता में है। प्रतिस्पर्धा दोनों देशों की वास्तविकता है, लेकिन उसे जिम्मेदार प्रबंधन की आवश्यकता है। दुनिया को ऐसी कूटनीति की जरूरत है जिसमें मतभेदों को समाप्त करने के बजाय उन्हें नियंत्रित किया जाए और सहयोग के संभावित क्षेत्रों को विस्तार दिया जाए। अमेरिका और चीन के बीच संबंध आने वाले समय में भी उतार-चढ़ाव से गुजरेंगे। इस परिस्थिति में दोनों देशों के नेतृत्व की परीक्षा इस बात से होगी कि वे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए संवाद, पारस्परिक सम्मान और स्थिरता के लिए कितनी जगह बनाते हैं। हालिया वार्ता ने कम से कम यह संकेत दिया है कि प्रतिस्पर्धा के बीच बातचीत का दरवाजा खुला रखना दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है।

विजया पाठक


क्या है E20, कंपनियां और 1.72 लाख करोड़ की सरकारी खरीद का पूरा कनेक्शन?
गडकरीजी ! पुत्रमोह में क्यों मेरी बलि चढ़ा रहे हो....
एथेनॉल
एथेनॉल को लेकर देश में मचा हाहाकार: सवाल ईंधन का ही नहीं, भरोसे का भी
एथेनॉल की अर्थव्यवस्था में गडकरी परिवार

सवाल सिर्फ इतना नहीं कि केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी परिवार एथेनॉल कारोबार में है, असली सवाल है- नीति, बाजार और कारोबारी हित एक-दूसरे से कितने जुड़े हैं? भारत की ऊर्जा नीति में एथेनॉल अब कोई छोटा प्रयोग नहीं है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति ने पिछले एक दशक में एक बड़े औद्योगिक बाजार का रूप ले लिया है। सरकारी तेल कंपनियां हजारों करोड़ रुपये का एथेनॉल खरीद रही हैं और देश में सैकड़ों उत्पादन इकाइयां इस बाजार से जुड़ चुकी हैं। इसी तेजी से बढ़ते बाजार के बीच एक राजनीतिक और कारोबारी सवाल लगातार उठ रहा है। क्या एथेनॉल नीति को जोर-शोर से आगे बढ़ाने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के परिवार का एथेनॉल कारोबार इस नीति से आर्थिक रूप से लाभान्वित हो रहा है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गडकरी के बेटे निखिल गडकरी CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd. के Managing Director हैं, जबकि गडकरी परिवार से जुड़ी Manas Agro Industries & Infrastructure Ltd. भी चीनी, डिस्टिलरी और एथेनॉल जैसे कारोबार में है। लेकिन दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है- सिर्फ यह तथ्य कि किसी मंत्री के परिवार की कंपनी उस क्षेत्र में कारोबार करती है, अपने आप में सरकारी नीति से अनुचित लाभ साबित करता है। भारत में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाने की नीति अब महज वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग नहीं रह गई है। पिछले एक दशक में एथेनॉल ब्लेंडिंग तेजी से बढ़ी है और इसके साथ चीनी मिलों, डिस्टिलरी, अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्रों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के बीच एक बड़ा कारोबारी तंत्र खड़ा हुआ है। इसी विस्तार के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के परिवार से जुड़े कारोबार और एथेनॉल नीति के बीच संबंधों को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हुई है। मूल सवाल यह नहीं है कि गडकरी परिवार से जुड़ी कंपनियां एथेनॉल कारोबार में हैं या नहीं। उपलब्ध कॉरपोरेट रिकॉर्ड और संबंधित रिपोर्टों में इसका उल्लेख मिलता है। असली सवाल यह है कि इस तेजी से बढ़ते बाजार में इन कंपनियों का कारोबार कितना है, सरकारी तेल कंपनियों से उन्हें कितना कारोबार मिलता है और E20 जैसी नीतियों के विस्तार से उनके कारोबारी हितों पर क्या असर पड़ता है। एथेनॉल को लेकर देश में उठ रहा शोर केवल तकनीकी विवाद नहीं है। यह ऊर्जा सुरक्षा, किसान अर्थव्यवस्था, वाहन तकनीक, उपभोक्ता अधिकार और नीति की पारदर्शिता से जुड़ा प्रश्न बन गया है। सरकार के पास E20 के समर्थन में वैज्ञानिक परीक्षण और बड़े पैमाने के उपयोग के आंकड़े हैं, जबकि उपभोक्ताओं के बीच माइलेज और पुराने वाहनों की अनुकूलता को लेकर चिंताएं हैं। उपलब्ध प्रमाणों से देश भर में बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने की बातें हो रही हैं। आखिरकार बहस का केंद्र यही होना चाहिए- एथेनॉल नीति से देश को जितना नुकसान हो रहा है, आम वाहन मालिकों पर पड़ने वाली वास्तविक लागत कितनी है? भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति अब केवल ऊर्जा नीति का विषय नहीं रह गई है। E20 यानी लगभग 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर वाहन मालिकों, परिवहन क्षेत्र, राजनीतिक दलों और सरकार के बीच बहस तेज हुई है। एक तरफ सरकार इसे कच्चे तेल के आयात में कमी, विदेशी मुद्रा बचत और किसानों के लिए अतिरिक्त बाजार से जोड़ती है, दूसरी तरफ वाहन मालिकों की शिकायतें माइलेज, पुराने वाहनों की अनुकूलता और ईंधन के विकल्प को लेकर हैं। विवाद का सबसे बड़ा कारण

वाहन मालिकों की यह चिंता है कि E20 से माइलेज कम हो सकता है और पुराने वाहनों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। कुछ वाहन मालिकों ने कम ईंधन दक्षता और वाहन के हिस्सों पर अधिक घिसावट की शिकायतें कीं। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से ऊर्जा सुरक्षा और पेट्रोलियम आयात में कमी जैसे संभावित लाभ हैं, लेकिन उपभोक्ता के दृष्टिकोण से माइलेज, वाहन की अनुकूलता, ईंधन की गुणवत्ता और वास्तविक प्रति किलोमीटर खर्च महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसलिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का मूल्यांकन केवल पेट्रोल सस्ता हुआ या महंगा के आधार पर नहीं, बल्कि वाहन के प्रदर्शन, ईंधन की खपत और दीर्घकालिक लागत को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ देखा जाये तो मोदी सरकार भी इस गंभीर मुददे पर मौन धारण किये हुए है। विपक्ष और आमजन एथेनॉल नीति को लेकर हमलावर है वहीं सरकार के कान में जूँ तक नहीं रेंग रही है। आखिर इस प्रयोग को लेकर मोदी सरकार संतुष्ट क्यों नजर आ रही है। देश में एथेनॉल उत्पादन की क्षमता तेजी से बढ़कर 2000 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष से ज्यादा हो गई है। एथेनॉल का यह उत्पादन 478 महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में लगे संयंत्रों में किया जा रहा है। जबकि पेट्रोल वाहनों में एथेनॉल मिला पेट्रोल उपयोग करने से वाहन खराब हो रहे हैं। इस कारण मौजूदा मांग उत्पादन से कम बनी हुई है। बावजूद उदयोगपति एथेनॉल निर्माण के नए संयंत्रों के निर्माण में लगे हैं। इस सेक्टर को बैंकों ने एक लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है। अब सरकार की दुविधा यह है कि यदि पेट्रोल में ब्लेंडिंग घटाई गई तो हजारों करोड़ के बैंक ऋण और देसी-विदेशी निवेश डूबने का संकट बढ़ जाएगा। ब्लेंडिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं, जिसके तहत एक तय मात्रा में बायो फ्यूल, यानी E-20 या E-10 प्रतिशत पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है। हालांकि यह जीवाश्म ईंधन जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल है। इस जैव ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा माना जाता है। इस कारण दुनिया के देश जैव ईंधन का उत्पादन बढ़ाने में लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अंत तक एथेनॉल उत्पादन क्षमता 400 करोड़ लीटर और बढ़ जाएगी। अर्थात कुल उत्पादन क्षमता करीब 2400 करोड़ लीटर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। जबकि 2014 में एथेनॉल का उत्पादन 421 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष होता था। जो अब चार गुना अधिक हो गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए E20 पेट्रोल के लिए 1200 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। यही नहीं उद्योगों, फार्मा कंपनियों और रसायन क्षेत्रों में भी अधिकतम 350 लीटर एथेनाल की मांग बनी हुई है। 2025 से देशभर में E20 पेट्रोल की बिक्री हो रही है। पश्चिम एशिया में चल रहे अमेरिका-ईरान, रूस-यूक्रेन और इजरायल के युद्धों के चलते केंद्र सरकार ने मजबूरी में अप्रैल 2026 से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बाजार में देने की शुरुआत की है। इधर एथेनॉल के नए संयंत्र लगाए जाने के कारण उद्योग जगत की मांग है कि E-30 या उससे अधिक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री देश भर में शुरू की जाए। फिलहाल देश में गन्ना, मक्का और अन्य अनाजों से बने एथेनॉल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए। क्योंकि यदि खाद्य सामग्री से बना एथेनॉल निर्यात होने लग जाएगा तो देश में खाने वाला अनाज की आपूर्ति में तो आएगी ही, उम्मीद से ज्यादा अनाज महंगा भी हो जाएगा।

एथेनॉल को लेकर देश में मचा हाहाकार, एथेनॉल की अर्थव्यवस्था में गडकरी परिवार

विजया पाठक

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल भारत की ऊर्जा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसके कई संभावित आर्थिक और ऊर्जा संबंधी लाभ हैं, लेकिन वाहन मालिकों के लिए इसके तकनीकी प्रभावों को समझना भी आवश्यक है। अधिक एथेनॉल वाले मिश्रण में कम ऊर्जा सामग्री के कारण माइलेज में कमी, पुराने वाहनों के कुछ ईंधन-प्रणाली घटकों की अनुकूलता, नमी और ईंधन गुणवत्ता जैसी बातें महत्वपूर्ण हैं। दूसरी ओर, आधुनिक और उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए वाहन निर्धारित एथेनॉल मिश्रण का इस्तेमाल करने के लिए बनाए जा सकते हैं। इसलिए एथेनॉल को लेकर यह कहना कि इससे सभी गाड़ियों को नुकसान होता है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। इसी तरह यह मान लेना भी उचित नहीं है कि हर वाहन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही निष्कर्ष वाहन के मॉडल, निर्माण वर्ष, इंजन डिजाइन और निर्माता की अनुशंसा के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। आम वाहन मालिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होना चाहिए कि उसकी गाड़ी किस एथेनॉल मिश्रण के लिए प्रमाणित है और उस मिश्रण से वास्तविक प्रति किलोमीटर खर्च तथा वाहन के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।

भारत में पेट्रोल में एथेनॉल का उपयोग पिछले एक दशक में 1.53 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 20 प्रतिशत हो गया है। यह देश के ईंधन बाजार में एक बड़ा बदलाव है। इसके पीछे कच्चे तेल के आयात को कम करना, विदेशी मुद्रा बचाना, किसानों को





बाजार देना और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य हैं। लेकिन इस नीति का मूल्यांकन केवल मिश्रण प्रतिशत देखकर नहीं किया जा सकता। वाहन का माइलेज, पुराने वाहनों की अनुकूलता, एथेनॉल की कीमत, कृषि में पानी और भूमि का उपयोग, चीनी तथा मक्का की कीमतें और आम उपभोक्ता की प्रति किलोमीटर ईंधन लागत भी महत्वपूर्ण विषय हैं। इसलिए एथेनॉल

बड़ा सवाल : क्या गडकरी परिवार के लिए वरदान साबित हो रहा ऐथानॉल?

नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd. के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कंपनी एग्रो प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग और एथेनॉल सहित कई क्षेत्रों में कारोबार करती है। 2024 में कंपनी ने एथेनॉल उत्पादन पर अपना फोकस बढ़ाया। कंपनी की गतिविधियों में एथेनॉल का उत्पादन और तेल विपणन कंपनियों को उसकी बिक्री शामिल है। 2026 में एथेनॉल को लेकर सरकार की नीतियों और प्रस्तावित उच्च ब्लेंडिंग स्तरों की चर्चा के बीच CIAN Agro के शेयर में भी तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गडकरी परिवार से जुड़ी Manas Agro Industries भी एथेनॉल कारोबार में है। यह कंपनी पुराने Purti Group से अलग होकर बनी और इसका संचालन नितिन गडकरी के बेटे सारंग गडकरी से जुड़ा है। कंपनी का प्रमुख कारोबार चीनी,



मिश्रण भारत की ऊर्जा नीति में एक बड़ा परिवर्तन है, लेकिन इसके लाभ और लागत दोनों को आंकड़ों के आधार पर देखना आवश्यक है।

एथेनॉल की कहानी अचानक शुरू नहीं हुई



एथेनॉल और उससे जुड़े उत्पादों में है। दिलचस्प बात यह है कि गडकरी परिवार का एथेनॉल कारोबार कोई हालिया गतिविधि नहीं है। 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन Purti Sugar ने एथेनॉल उत्पादन के लिए Praj Industries के साथ समझौता किया था। प्रस्तावित संयंत्र में कृषि अवशेषों से एथेनॉल बनाने की तकनीक का इस्तेमाल होना था।

विवाद का मूल सवाल यह है: जब सरकार पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की नीति को आगे बढ़ा रही हो और उसी समय संबंधित केंद्रीय मंत्री के परिवार की कंपनियां एथेनॉल कारोबार में हों, तो क्या यहां हितों के टकराव का सवाल उठता है? यह सवाल उठना और यह साबित होना कि किसी कंपनी को सरकारी नीति के कारण अनुचित लाभ मिला- दो अलग बातें हैं।

इसलिए जांच के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल सामने आते हैं:

- गडकरी परिवार से जुड़ी कंपनियों ने सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को कितनी मात्रा में एथेनॉल बेचा?
- उन्हें किस कीमत पर एथेनॉल खरीद अनुबंध मिले?
- इन कंपनियों का एथेनॉल कारोबार पिछले वर्षों में कितना बढ़ा?
- E20 या भविष्य के उच्च एथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य से इन कंपनियों की उत्पादन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
- क्या नीति निर्माण की प्रक्रिया में गडकरी की कोई प्रत्यक्ष प्रशासनिक भूमिका थी?
- क्या संबंधित कंपनियों को सरकारी नीति के कारण कोई ऐसा विशेष लाभ मिला जो अन्य एथेनॉल उत्पादकों को उपलब्ध नहीं था?
- इन सवालों के दस्तावेजी जवाब ही यह स्पष्ट कर सकते हैं कि

भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम नया नहीं है। सरकार के अनुसार इसका पायलट 2001 में शुरू हुआ था और 2013-14 में पेट्रोल में औसत एथेनॉल मिश्रण लगभग 1.53 प्रतिशत था। यह बढ़कर 2024-25 में करीब 19.2 प्रतिशत

मामला सामान्य कारोबारी संयोग है या वास्तविक हित संबंध का प्रश्न।

गडकरी के बेटे का एथेनॉल कारोबार: 2013 से 2026 तक

2013 से शुरू हुई कहानी 2026 में E20 विवाद तक कैसे पहुंची?

भारत में एथेनॉल केवल वैकल्पिक ईंधन का कारोबार नहीं रह गया है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य बढ़ने के साथ यह चीनी मिलों, डिस्टिलरी और अनाज आधारित एथेनॉल कंपनियों के लिए बड़ा बाजार बन गया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के परिवार से जुड़ी कंपनियों का एथेनॉल कारोबार चर्चा में आया। यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि परिवार की कंपनियां एथेनॉल बनाती हैं या नहीं। यह तथ्य सार्वजनिक कॉरपोरेट रिकॉर्ड में मौजूद है। असली सवाल यह है कि इन कंपनियों का कारोबार कितना बड़ा है, उन्हें सरकारी तेल कंपनियों से कितना कारोबार मिलता है और E-20 नीति से उनका वास्तविक आर्थिक लाभ कितना है।

2013 में भारत का एथेनॉल बाजार कितना छोटा था?

वर्ष	औसत एथेनॉल ब्लेंडिंग
2013-14	1.53 प्रतिशत
2020-21	7.93 प्रतिशत
2022-23	12.06 प्रतिशत
2023-24	14.60 प्रतिशत
2024-25	17.98 प्रतिशत
2025-26	लगभग 20 प्रतिशत

2013: एथेनॉल से गडकरी का पुराना जुड़ाव

एथेनॉल के साथ गडकरी परिवार का कारोबारी जुड़ाव 2024 से शुरू नहीं हुआ। दिसंबर 2013 में नितिन गडकरी से जुड़े Purti Sugar ने Praj Industries के साथ एक नई पीढ़ी के एथेनॉल प्लांट के लिए समझौता किया था। उस समय प्रस्तावित प्लांट की लागत करीब 80 करोड़ और क्षमता 30,000 लीटर प्रतिदिन बताई गई थी। इसमें गन्ने के अवशेष यानी bagasse तथा कृषि अपशिष्ट से एथेनॉल बनाने की योजना थी। उसी कार्यक्रम में गडकरी ने पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने की वकालत भी की थी। यानी एथेनॉल गडकरी परिवार के कारोबारी विमर्श में E20 लागू होने से काफी पहले मौजूद था।

2026 में कारोबार और बड़ा हुआ

वित्तीय वर्ष 2025-26 के उपलब्ध वित्तीय विवरण के अनुसार CIAN Agro की standalone revenue from operations और 2025-26 में उपलब्ध अवधि के दौरान करीब 20 प्रतिशत पहुंच गया। यानी एक दशक से कुछ अधिक समय में पेट्रोल में एथेनॉल का हिस्सा कई गुना बढ़ा है। इसी तेज बदलाव ने अब बहस को जन्म दिया है।

CIAN Agro में निखिल गडकरी की भूमिका



निखिल गडकरी CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd. के Managing Director हैं। कंपनी का कारोबार केवल एथेनॉल तक सीमित नहीं है। इसमें Agro/FMCG, healthcare, infrastructure और अन्य गतिविधियां भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण बदलाव 2024 के आसपास आया, जब कंपनी ने एथेनॉल कारोबार पर अपना फोकस बढ़ाया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार CIAN ने IOC, BPCL और HPCL जैसी तेल विपणन कंपनियों को टेंडर व्यवस्था के माध्यम से एथेनॉल बेचने की गतिविधि शुरू की।

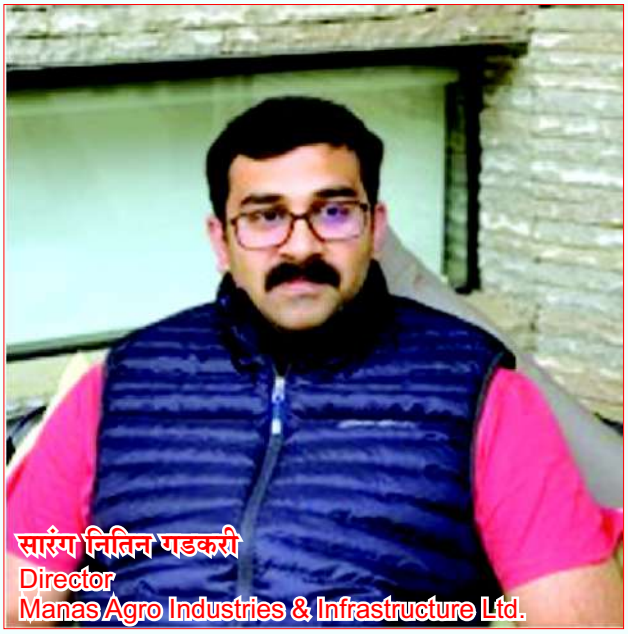
लगभग 414.75 करोड़ रही। वहीं consolidated revenue from operations लगभग 2,234.35 करोड़ तक पहुंच गई। इसलिए 2024 से 2026 के बीच कंपनी का आकार बढ़ना वास्तविक है। कंपनी ने इस अवधि में कई व्यवसायों और subsidiaries को अपने समूह में जोड़ा।

Manas Agro का पैसा भी कहानी का हिस्सा है

यहां कहानी और दिलचस्प हो जाती है। CIAN की वित्तीय वर्ष 2024-25 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार Manas Agro Industries & Infrastructure Ltd. CIAN की step-down subsidiary बन गई। Manas Agro के कारोबार में शामिल हैं:, Sugar manufacturing, Power generation, Distillery, Ethanol production, E10 trading LPG, वित्तीय वर्ष 2024-25 में Manas Agro का operating revenue लगभग 913.63 करोड़ और लाभ लगभग 5.27 करोड़ बताया गया है। यानी अब CIAN और Manas को केवल दो पूरी तरह अलग कारोबारी कहानियों की तरह देखना भी अधूरा होगा। 2026 की CIAN filing में भी Manas Agro को CIAN Group की step-down subsidiary के रूप में दिखाया गया है।

Manas Agro भी महत्वपूर्ण कड़ी

इस कहानी की दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी Manas Agro Industries & Infrastructure Ltd. है। उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट संबंधी सामग्री के अनुसार Manas Agro, CIAN की step-down



सारंग नितिन गडकरी
Director
Manas Agro Industries & Infrastructure Ltd.

subsidiary बनी। इसके कारोबार में चीनी, बिजली उत्पादन, डिस्टिलरी, एथेनॉल उत्पादन और E10 ट्रेडिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में Manas Agro का operating revenue करीब 913.63 करोड़ रुपये और लाभ करीब 5.27 करोड़ रुपये बताया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि



Manas Agro Industries & Infrastructure Ltd.

माइलेज का सवाल

एथेनॉल की ऊर्जा सामग्री पेट्रोल से कम होती है। इसलिए E-20 जैसे मिश्रण से कुछ परिस्थितियों में समान दूरी के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता हो सकती है। सरकार ने भी पहले स्वीकार किया है कि

एथेनॉल से जुड़ी कारोबारी गतिविधियां केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जुड़े हुए कारोबारी ढांचे का हिस्सा हैं। 2012 के NCLT/IBBI दस्तावेज में Manas Agro को चीनी, बिजली, rectified spirits, extra neutral alcohol और ethanol से संबंधित कंपनी के रूप में दर्ज किया गया था तथा सारंग नितिन गडकरी को whole-time director के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

2013 में ही शुरू हो गया था एथेनॉल कनेक्शन

गडकरी परिवार और एथेनॉल का कारोबारी संबंध E20 के मौजूदा विवाद से काफी पुराना है। 2013 में गडकरी से जुड़े Purti Sugar ने Praj Industries के साथ एथेनॉल उत्पादन से संबंधित समझौता किया था। उस समय भारत में पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग आज की तुलना में बहुत कम थी। जब एथेनॉल को लेकर गडकरी लंबे समय से सार्वजनिक रूप से नीति का समर्थन कर रहे थे, तब परिवार का कारोबारी विस्तार किस तरह आगे बढ़ा? भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग लगातार बढ़ती गई। 2013-14 में पेट्रोल में औसत एथेनॉल ब्लेंडिंग करीब 1.53 प्रतिशत थी। इसके बाद सरकार ने लक्ष्य लगातार आगे बढ़ाए और 20 प्रतिशत ब्लेंडिंग लक्ष्य को 2030 से खिसकाकर ESY 2025-26 तक कर दिया। 2025-26 तक देश लगभग 20 प्रतिशत blending स्तर तक पहुंच गया। इस नीति के साथ एथेनॉल की सरकारी खरीद भी तेजी से बढ़ी। राज्यसभा में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों- IOC, BPCL और HPCL ने तीन Ethanol Supply Years में 2,417.78 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदा, जिसकी कीमत लगभग 1.72 लाख करोड़ रही।

पेट्रोल में एथेनॉल का उपयोग और नितिन गडकरी से जुड़े लाभ के सवाल

भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा और पेट्रोलियम क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नीति बन गई है। सरकार का तर्क है कि एथेनॉल मिश्रण से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहन देने में मदद मिल सकती है। दूसरी ओर, इस नीति को लेकर वाहन मालिकों के माइलेज, वाहन की अनुकूलता और एथेनॉल उत्पादन से जुड़े कारोबारी हितों पर भी सवाल उठे हैं। इसी संदर्भ में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की भूमिका पर राजनीतिक बहस हुई है। सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि गडकरी

1.72 लाख करोड़ रूपये का बाजार

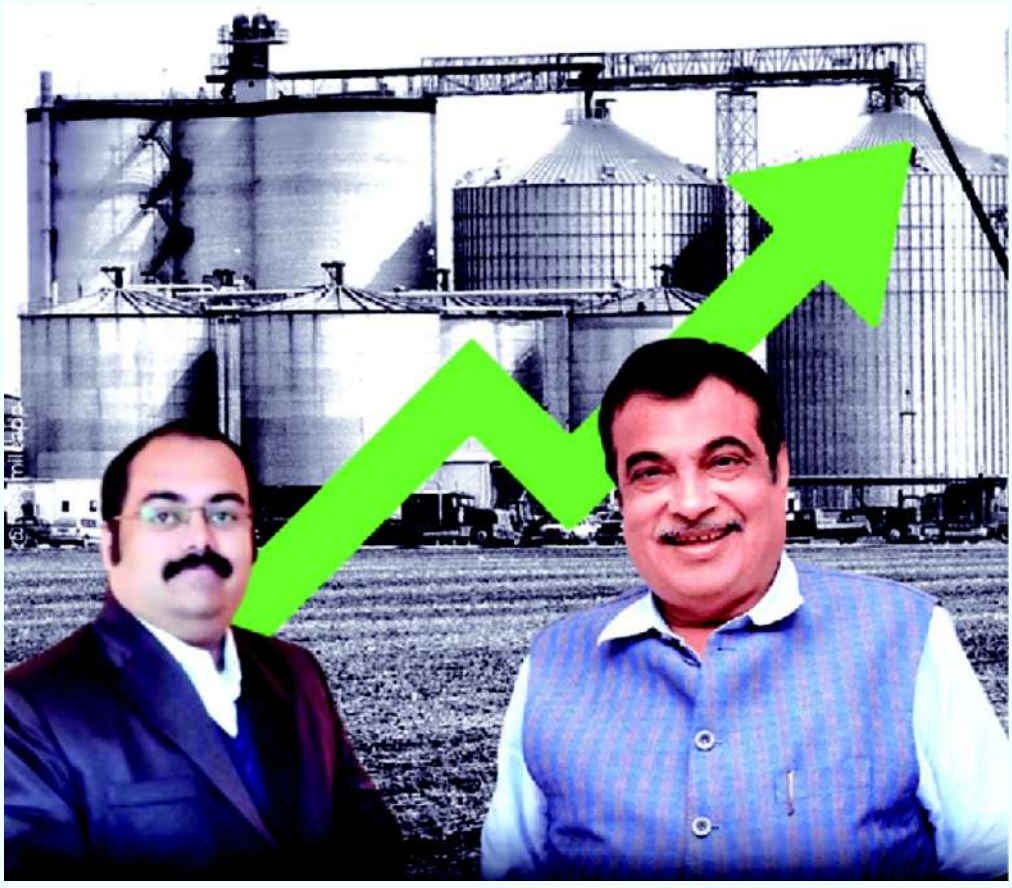


एथेनॉल कारोबार को समझने के लिए सरकारी खरीद का आकार देखना जरूरी है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने तीन एथेनॉल सप्लाई वर्षों में 2,417.78 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदा और इसकी कीमत करीब 1.72 लाख करोड़ रुपये रही। इनमें 2023-24 में खरीद पर करीब 48,757 करोड़ रुपये, 2024-25 में करीब 73,996 करोड़ रुपये और 2025-26 में जून तक करीब 49,577 करोड़ रुपये का व्यय बताया गया है। यही वह बिंदु है जहां एथेनॉल नीति केवल ऊर्जा नीति नहीं रह जाती। यह हजारों करोड़ रुपये के सरकारी खरीद बाजार में बदल जाती है।

E10 के लिए डिजाइन किए गए और E20 के लिए कैलिब्रेट किए गए चार-पहिया वाहनों में ईंधन दक्षता में मामूली कमी हो सकती है। यही कारण है कि आम वाहन मालिक का सवाल केवल यह नहीं है कि पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर कितनी है,

के परिवार से जुड़े कारोबारी समूह चीनी और एथेनॉल कारोबार से जुड़े रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने इसे संभावित हितों के टकराव का मामला बताते हुए आरोप लगाया कि एथेनॉल को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीति से उनके परिवार से जुड़े कारोबार को आर्थिक फायदा हो सकता है।

एथेनॉल नीति का विस्तार



भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने जून 2022 में 10 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया था। इसके बाद मिश्रण बढ़ता गया और 2024-25 में फरवरी 2025 तक यह लगभग 17.98 प्रतिशत पहुंच गया। सरकार ने 20 प्रतिशत मिश्रण के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाया। गडकरी लंबे समय से पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में एथेनॉल तथा अन्य वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग की वकालत करते रहे हैं। 2021 में उन्होंने एथेनॉल को आयात का विकल्प, स्वदेशी ईंधन और कम प्रदूषण वाला ईंधन बताया था तथा किसानों की आय बढ़ने की बात कही थी।

गडकरी के परिवार के कारोबार का सवाल

विवाद का मुख्य बिंदु यह है कि गडकरी के परिवार से जुड़े कारोबारी हित चीनी और एथेनॉल क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। 2025 में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गडकरी के बेटों से जुड़ी कंपनियों को एथेनॉल कारोबार के विस्तार से लाभ हो रहा है और इसलिए नीति तथा निजी कारोबारी हितों के बीच संभावित हितों के टकराव की जांच होनी चाहिए। हालांकि, यह आरोप है, स्थापित तथ्य नहीं कि गडकरी ने अपनी सरकारी भूमिका का इस्तेमाल व्यक्तिगत या पारिवारिक आर्थिक लाभ के लिए किया। गडकरी ने इन आरोपों को खारिज किया है। जुलाई 2026 में उन्होंने कहा कि उनके परिवार का चीनी कारोबार एथेनॉल नीति के विस्तार से पहले से मौजूद था और उनके बेटों द्वारा संचालित कारोबार में एथेनॉल का हिस्सा सीमित है। उन्होंने यह कहा कि एथेनॉल की कीमत और खरीद संबंधी निर्णय उनके मंत्रालय के बजाय पेट्रोलियम मंत्रालय और केंद्र सरकार की संबंधित

बल्कि यह भी है कि एक लीटर E-20 से गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है।

पुराने वाहनों की चिंता

पुराने वाहनों को लेकर विवाद अधिक संवेदनशील है। वाहन की ईंधन प्रणाली में रबर, प्लास्टिक, सील और गैस्केट जैसी



व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं।

क्या वास्तव में व्यक्तिगत लाभ हुआ?

इस प्रश्न का उत्तर देते समय दो अलग-अलग बातों को अलग रखना जरूरी है- नीति से किसी उद्योग को आर्थिक लाभ मिलना और किसी मंत्री को व्यक्तिगत आर्थिक लाभ मिलना। एथेनॉल मिश्रण बढ़ने से एथेनॉल उत्पादकों, चीनी मिलों और कृषि क्षेत्र के लिए बाजार का विस्तार होता है। सरकार स्वयं कहती है कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गन्ने के बकाये और मक्का उत्पादन की व्यवहार्यता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

लेकिन इससे यह अपने आप साबित नहीं होता कि गडकरी या उनके परिवार को सरकारी नीति के कारण अनुचित व्यक्तिगत लाभ मिला। उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों में गडकरी ने ऐसे लाभ से इनकार किया है और उनके खिलाफ लगाए गए हितों के टकराव के आरोपों को खारिज किया है।

पारदर्शिता क्यों जरूरी है?

जब किसी मंत्री की सार्वजनिक नीति और उनके परिवार से जुड़े कारोबारी क्षेत्र में समानता दिखाई देती है, तो जनता के सामने पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होना चाहिए कि नीति किस आधार पर बनाई गई, एथेनॉल की कीमत कौन तय करता है, सरकारी खरीद किन नियमों के तहत होती है और संबंधित कंपनियों को इससे कितना व्यावसायिक लाभ मिलता है। साथ ही, आरोपों और प्रमाणित तथ्यों के बीच अंतर करना भी जरूरी है। केवल किसी परिवार का किसी उद्योग में कारोबार होना अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है। दूसरी ओर, यदि किसी नीति से संबंधित वास्तविक हितों का टकराव हो, तो उसकी स्वतंत्र जांच और सार्वजनिक जानकारी लोकतांत्रिक जवाबदेही को मजबूत कर सकती

सामग्रियां होती हैं। इनकी एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों के साथ अनुकूलता वाहन के मॉडल और निर्माण वर्ष पर निर्भर कर सकती है।

देश को क्या लाभ बताया जा रहा है?

सरकार के अनुसार एथेनॉल से कच्चे



तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 2025 तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार E-20 कार्यक्रम से लाखों टन कच्चे तेल के बराबर आयात प्रति स्थापित हुआ और विदेशी मुद्रा की बचत हुई। साथ ही एथेनॉल के लिए गन्ने और अनाज की खरीद से किसानों के लिए अतिरिक्त बाजार तैयार हुआ। एथेनॉल उत्पादन क्षमता भी काफी बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2026



20 प्रतिशत मिश्रण का मतलब क्या है?

E20 का अर्थ है कि पेट्रोल में लगभग 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल है। सरकार ने 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य पहले 2030 के लिए रखा था, लेकिन बाद में इसे एथेनॉल सप्लाई वर्ष 2025-26 तक आगे कर दिया गया। 2025-26 में 20 प्रतिशत औसत मिश्रण हासिल होने के साथ भारत ने इस लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले पूरा किया। सरकार के अनुसार 2025-26 में एथेनॉल की खरीद 1,200 करोड़ लीटर से अधिक रहने का अनुमान है।

पेट्रोल की जगह कितना एथेनॉल?

20ऽ मिश्रण का अर्थ यह नहीं है कि देश के हर पेट्रोल पंप पर हर समय बिल्कुल 20 प्रतिशत एथेनॉल ही मौजूद है। यह औसत मिश्रण है, जो तेल विपणन कंपनियों की खरीद और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। सरकार के 2023 के रोडमैप में 2025-26 में 20 प्रतिशत मिश्रण के लिए लगभग 1,016 करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। इसका सीधा अर्थ है कि बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम ईंधन की जगह घरेलू रूप से उत्पादित एथेनॉल का उपयोग किया जा रहा है।

में उत्पादन क्षमता करीब 2,000 करोड़ लीटर तक पहुंच चुकी थी।

फिर जनता का गुस्सा क्यों?

यहां मुद्दा केवल एथेनॉल नहीं, बल्कि नीति की पारदर्शिता और उपभोक्ता के विकल्प का भी है। यदि किसी वाहन मालिक की गाड़ी E-20 के लिए डिजाइन नहीं की गई है, तो उसका सवाल

क्या इससे चीनी महंगी होती है?

सैद्धांतिक रूप से यदि चीनी उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा एथेनॉल के लिए इस्तेमाल हो और घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता कम हो जाए, तो कीमत बढ़ने का दबाव पैदा हो सकता है। बाजार में किसी वस्तु की आपूर्ति घटने और मांग स्थिर या बढ़ने पर कीमत बढ़ सकती है। लेकिन हर चीनी मूल्य वृद्धि को एथेनॉल के कारण बताना सही नहीं होगा। अगस्त 2026 में सरकार के अनुसार चीनी के दाम में हालिया तेजी के पीछे घरेलू उत्पादन में कमी, त्योहारी मांग, मौसम से गन्ने की फसल को नुकसान, वैश्विक चीनी आपूर्ति में कमी तथा कुछ हिस्सों में जमाखोरी और सट्टेबाजी जैसे कई कारण रहे। सरकार के अनुसार 2025-26 में एथेनॉल के लिए मोड़ी गई चीनी की हिस्सेदारी लगभग 09 प्रतिशत रही, जो 2022-23 में लगभग 12 प्रतिशत थी। साथ ही, देश में बनने वाले एथेनॉल का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा अब अनाज, विशेषकर मक्का, से आता है।



फिर चीनी के दाम क्यों बढ़े?: 2026 में चीनी उत्पादन शुरुआती अनुमान से कम रहने की बात सरकार ने कही है। अगस्त 2026 के आंकड़ों के अनुसार उत्पादन लगभग 306 लाख टन रहने का अनुमान था, जबकि शुरुआती अनुमान लगभग 343 लाख टन था। गन्ने की फसल को रोग और अत्यधिक बारिश से हुए जलभराव जैसे कारणों से नुकसान पहुंचा। इसी अवधि में अंतरराष्ट्रीय चीनी कीमतों में भी वृद्धि हुई। इसलिए घरेलू कीमतों को केवल एथेनॉल नीति से जोड़ना पूरी तस्वीर नहीं बताता।

स्वाभाविक है कि उसे कौनसा ईंधन उपलब्ध होगा। 2026 में इस विषय पर बहस इसलिए भी बढ़ी क्योंकि E-20 की देशव्यापी उपलब्धता ने उपभोक्ताओं के लिए पुराने कम-एथेनॉल विकल्पों को लेकर चिंता पैदा की। यहीं से सवाल उठता है- क्या उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उसकी गाड़ी किस मिश्रण के लिए प्रमाणित है? क्या पंप पर ईंधन की जानकारी पर्याप्त रूप से प्रदर्शित है? और यदि माइलेज में अंतर आता है तो उसकी वास्तविक आर्थिक लागत कितनी है?

गुणवत्ता पर भी उठे सवाल

E-20 को लेकर नमी और क्लोराइड जैसे प्रदूषण की चर्चाएं भी हुईं। अगस्त 2026 में सरकारी तेल कंपनियों ने देश भर में परीक्षण के बाद कहा कि E-20 ईंधन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के भीतर है। 100

एथेनॉल नीति का दूसरा पक्ष: एथेनॉल के लिए चीनी या गन्ने के उत्पादों का इस्तेमाल करने से चीनी मिलों को एक वैकल्पिक बाजार मिलता है। सरकार के अनुसार, इससे मिलों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई और किसानों के गन्ना भुगतान में मदद मिली। अगस्त 2026 तक 2025-26 सीजन के 97 प्रतिशत गन्ना बकाये का भुगतान हो चुका था।



पहले जब देश में चीनी का अतिरिक्त उत्पादन होता था, तो बड़ी मात्रा में स्टॉक मिलों के पास पड़ा रहता था। सरकार ने इसी समस्या को कम करने के लिए एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया। 2020 में सरकार ने बताया था कि सामान्य परिस्थितियों में घरेलू उत्पादन खपत से लगभग 60 लाख टन अधिक रहता था और इस अतिरिक्त स्टॉक के कारण मिलों की बड़ी रकम फंस जाती थी।

आम उपभोक्ता के लिए सवाल: आम उपभोक्ता के दृष्टिकोण से मुख्य चिंता यह है कि यदि एथेनॉल उत्पादन के लिए खाद्य उपयोग वाली चीनी या गन्ने की अधिक मात्रा मोड़ी जाती है, तो भविष्य में चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर केवल एथेनॉल की मात्रा देखकर नहीं दिया जा सकता। चीनी उत्पादन, घरेलू खपत, निर्यात, सरकारी स्टॉक नीति, गन्ने का उत्पादन, मौसम, वैश्विक कीमत और एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाले वैकल्पिक कच्चे माल- इन सभी का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। सरकार ने भी 2025 के Sugar Control Order में एथेनॉल सहित ऐसे उत्पादों को नियामक दायरे में शामिल किया है, जो गन्ने से बनने वाली चीनी की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य घरेलू खपत के लिए पर्याप्त चीनी उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है।

से अधिक पेट्रोल नमूनों और 80 डिस्टिलरी से लिए गए एथेनॉल नमूनों की जांच का हवाला दिया गया तथा करीब 90,000 ईंधन स्टेशनों के भूमिगत टैंकों में पानी के प्रवेश की भी जांच की गई। इससे स्पष्ट है कि ईंधन की गुणवत्ता और आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी इस पूरी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

असली समाधान क्या है?

एथेनॉल पर बहस को एथेनॉल अच्छा है या खराब जैसे दो ध्रुवों में बांटने के बजाय कुछ स्पष्ट सवालों पर केंद्रित किया जाना चाहिए-

- किस मॉडल की गाड़ी किस एथेनॉल मिश्रण के लिए प्रमाणित है?
- E-20 से वास्तविक माइलेज पर कितना प्रभाव पड़ता है?
- पुराने वाहनों के रखरखाव की अतिरिक्त



एथेनॉल कहां से आता है?

भारत में एथेनॉल मुख्यतः गन्ने और उससे जुड़े उत्पादों तथा अनाज, विशेषकर मक्का, से बनाया जाता है। सरकार ने एथेनॉल के लिए कच्चे माल का आधार भी विस्तृत किया है ताकि केवल चीनी उद्योग पर निर्भरता न रहे। इससे चीनी मिलों को अतिरिक्त आय का स्त्रोत मिलता है और मक्का उत्पादकों के लिए भी बाजार बढ़ता है। दूसरी ओर, खाद्य फसलों और पानी के उपयोग को लेकर कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से जुड़े सवाल भी उठते हैं।

लागत कितनी है?

■ ईंधन की गुणवत्ता की नियमित स्वतंत्र जांच कैसे हो रही है?

■ उपभोक्ता को ईंधन के विकल्प और उसकी गुणवत्ता की पर्याप्त जानकारी मिल रही है या नहीं?

■ एथेनॉल नीति से किसानों, तेल कंपनियों, चीनी उद्योग और वाहन मालिकों को कितना आर्थिक लाभ या खर्च हो रहा है?



आम उपभोक्ताओं के लिए संभावित नुकसान

● **माइलेज पर असर:** एथेनॉल की ऊर्जा सामग्री पेट्रोल की तुलना में कम होती है। इसलिए समान मात्रा के ईंधन से वाहन को मिलने वाली ऊर्जा कुछ कम हो सकती है। इसका वास्तविक प्रभाव वाहन के इंजन, मिश्रण और ड्राइविंग परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

भारत में एथेनॉल का कितना उपयोग होता है?

वर्ष	पेट्रोल में औसत एथेनॉल मिश्रण	एथेनॉल की मात्रा
2013-14	1.53 प्रतिशत	करीब 38 करोड़ लीटर
2020-21	8.1 प्रतिशत	-
2022-23	12.06 प्रतिशत	500+ करोड़ लीटर
2023-24	14.60 प्रतिशत	करीब 672 करोड़ लीटर
2024-25	19.2 प्रतिशत	900+ करोड़ लीटर
2025-26	करीब 20 प्रतिशत	1,200 करोड़ लीटर से अधिक अनुमानित

2025-26 में 20 प्रतिशत मिश्रण हासिल होने के साथ पेट्रोल में एथेनॉल की खपत 1,000 करोड़ लीटर से काफी ऊपर पहुंच चुकी है। सरकार ने इस अवधि के लिए 1,200 करोड़ लीटर से अधिक एथेनॉल खरीद का अनुमान दिया है।

● **पुराने वाहनों में अनुकूलता:** अधिक एथेनॉल वाले मिश्रण के लिए सभी पुराने वाहनों के ईंधन तंत्र समान रूप से डिजाइन नहीं किए गए हैं। कुछ पुराने वाहनों में लंबे समय तक उपयोग करने पर ईंधन प्रणाली के कुछ घटकों पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ सकता है।

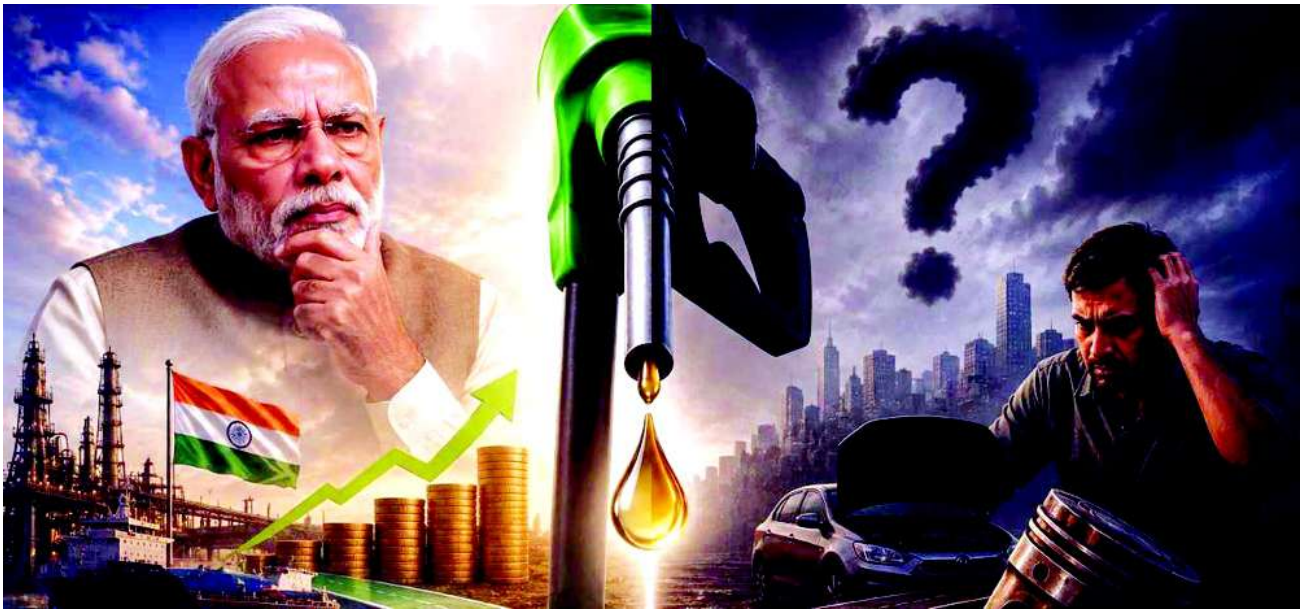
● **पानी सोखने की प्रवृत्ति:** एथेनॉल वातावरण से नमी अवशोषित कर सकता है। ईंधन में पानी की समस्या होने पर भंडारण और ईंधन प्रणाली से संबंधित दिक्कतें पैदा हो सकती हैं।

● **कीमत और वास्तविक बचत:** यदि एथेनॉल मिश्रण से प्रति लीटर कीमत कम भी हो, लेकिन माइलेज में कमी आती है, तो उपभोक्ता की वास्तविक प्रति किलोमीटर लागत अलग हो सकती है। इसलिए केवल प्रति लीटर कीमत देखकर लाभ का आकलन करना उचित नहीं है।

● **कृषि और पानी से जुड़े सवाल:** एथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाली फसलों की खेती में भूमि और पानी की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए बड़े पैमाने पर उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन भी जरूरी है।

● **उत्पादन और गुणवत्ता का महत्व:** एथेनॉल मिश्रण का लाभ तभी प्रभावी ढंग से मिल सकता है जब उत्पादन, परिवहन, भंडारण और पेट्रोल में मिश्रण के दौरान





निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन हो।

उपभोक्ता पर आर्थिक प्रभाव

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल प्रति किलोमीटर खर्च का है। यदि प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत कम हो, लेकिन वाहन का माइलेज भी कम हो जाए, तो वास्तविक बचत केवल पेट्रोल की प्रति लीटर कीमत देखकर तय नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, किसी वाहन को पहले एक लीटर पेट्रोल से जितनी दूरी मिलती थी, यदि मिश्रण बदलने के बाद थोड़ी कम दूरी मिलने लगे, तो वाहन मालिक को समान दूरी के लिए अधिक ईंधन खरीदना पड़ सकता है। इसलिए उपभोक्ता के लिए प्रति लीटर कीमत के साथ-साथ प्रति किलोमीटर ईंधन लागत देखना अधिक उपयोगी है।

एथेनॉल के उपयोग के तकनीकी नुकसान

एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से कुछ ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी लाभ हो सकते हैं, लेकिन उच्च एथेनॉल मिश्रण- जैसे E-20 के तकनीकी प्रभाव वाहन, इंजन डिजाइन और ईंधन प्रणाली की सामग्री पर निर्भर करते हैं। प्रमुख तकनीकी नुकसान इस प्रकार हैं:

पेट्रोल में एथेनॉल का उपयोग और चीनी की कीमतों में उछाल

भारत में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाने की नीति ने देश के चीनी उद्योग की अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है। गन्ने और उससे बनने वाले उत्पादों से एथेनॉल तैयार किया जाता है और उसे पेट्रोल में मिलाया जाता है। इससे चीनी मिलों को चीनी बेचने के अलावा एथेनॉल बेचकर भी आय का एक वैकल्पिक स्रोत मिलता है। लेकिन इस व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है- क्या पेट्रोल में एथेनॉल का बढ़ता उपयोग चीनी की उपलब्धता घटाकर उसकी कीमत बढ़ा सकता है?

चीनी से एथेनॉल की ओर बदलाव

एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस, चीनी सिरप, B-Heavy मोलासेस और

एथेनॉल और पेट्रोल में अंतर

एथेनॉल की ऊर्जा सामग्री पेट्रोल की तुलना में कम होती है। इसका अर्थ है कि समान मात्रा में एथेनॉल से पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा मिलती है। इसलिए एथेनॉल मिश्रण बढ़ने पर कुछ वाहनों में ईंधन की खपत बढ़ सकती है और माइलेज में कमी महसूस हो सकती है। E-20 जैसे मिश्रण में लगभग 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है। जो वाहन इस मिश्रण के लिए डिजाइन किए गए हैं, उनमें इसका इस्तेमाल सामान्य रूप से किया जा सकता है। लेकिन पुराने वाहन, जिन्हें कम एथेनॉल वाले ईंधन के लिए डिजाइन किया गया था, उनमें प्रभाव अलग हो सकता है।



कुछ परिस्थितियों में चीनी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार ने अतिरिक्त चीनी और गन्ने को एथेनॉल की ओर मोड़ने की नीति इसलिए अपनाई थी ताकि चीनी का अतिरिक्त भंडार कम हो, चीनी मिलों की नकदी स्थिति सुधरे और किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर किया जा सके। इस व्यवस्था का एक आर्थिक तर्क यह है कि जब देश में चीनी का उत्पादन घरेलू खपत से काफी अधिक होता है, तब अतिरिक्त चीनी के कारण मिलों की पूंजी फंस जाती है। एथेनॉल के लिए कुछ मात्रा मोड़ने से अतिरिक्त स्टॉक कम किया जा सकता है।

एथेनॉल की कहानी अचानक शुरू नहीं हुई

भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम नया नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इसका पायलट 2001 में शुरू हुआ और 2013-14 में पेट्रोल में औसत एथेनॉल मिश्रण लगभग 1.53 प्रतिशत था। इसके बाद मिश्रण लगातार बढ़ा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में यह करीब 8.1 प्रतिशत, 2021-22 में लगभग 10 प्रतिशत, 2022-23 में करीब 12 प्रतिशत, 2023-24 में 14.6 प्रतिशत और 2024-25 में लगभग 19.2 प्रतिशत रहा। 2025-26 में नवंबर 2025 से जून 2026 की उपलब्ध अवधि में औसत मिश्रण 20 प्रतिशत तक पहुंच गया। अर्थात एक दशक से अधिक समय में पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसी तेज परिवर्तन ने अब उपभोक्ता स्तर पर सवालों को भी बढ़ाया है।

क्या है E20, कंपनियां और 1.72 लाख करोड़ की सरकारी खरीद का पूरा कनेक्शन?

उपभोक्ता का सवाल: विकल्प कहां है?

E-20 नीति पर सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रश्न केवल तकनीकी नहीं, बल्कि उपभोक्ता विकल्प का भी है। यदि किसी पुराने वाहन के मालिक को अपने वाहन की E-20 अनुकूलता को लेकर संदेह है, तो उसे स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि उसका वाहन किस मिश्रण के लिए प्रमाणित है। भारत के मोटर वाहन नियमों में वाहन निर्माता द्वारा E12, E15, E20, E85 या E100 जैसे एथेनॉल मिश्रण स्तरों के लिए वाहन की compatibility को परिभाषित करने और उसे वाहन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का प्रावधान किया गया है। इस जानकारी को उपभोक्ता के लिए सरल,

स्पष्ट और आसानी से उपलब्ध बनाना इस पूरी नीति में महत्वपूर्ण है।

क्या 20 प्रतिशत से आगे जाएगा एथेनॉल?

फिलहाल सरकार ने कहा है कि पेट्रोल में राष्ट्रीय स्तर पर 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भविष्य में यदि ऐसा कोई निर्णय होता है तो सरकार के अनुसार उसे वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन तथा



वाहन निर्माताओं, तेल कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों सहित संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद लिया जाएगा। E85 अलग मामला है। इसे केवल उन Flex Fuel Vehicles के लिए पेश किया गया है जो इतने अधिक एथेनॉल वाले ईंधन के लिए विशेष रूप से डिजाइन और प्रमाणित हैं।

भारत में एथेनॉल के प्रमुख स्त्रोत कौन-से हैं?

भारत में ईंधन के लिए इस्तेमाल होने वाला एथेनॉल मुख्यतः दो बड़े स्त्रोतों से आता है-

पहला- गन्ना और चीनी उद्योग

गन्ने के रस, चीनी सिरप, B-Heavy Molasses और C-Heavy Molasses जैसे उत्पादों से एथेनॉल बनाया जाता है। कुछ परिस्थितियों में चीनी को भी एथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ा जा सकता है।

दूसरा- अनाज आधारित एथेनॉल

इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मक्का की है। इसके अलावा चावल और अन्य अनाजों से भी एथेनॉल बनाया जाता है। सरकार ने पिछले वर्षों में अनाज आधारित डिस्टिलरी को बढ़ावा दिया है ताकि देश केवल गन्ने पर निर्भर न रहे।

अब एथेनॉल का बड़ा हिस्सा मक्का से आता है

एथेनॉल नीति में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि भारत का एथेनॉल उत्पादन अब केवल चीनी उद्योग पर आधारित नहीं है। अगस्त 2026 की सरकारी जानकारी के अनुसार, देश में बनने वाले एथेनॉल का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा अब अनाज से आता है, जिसमें मक्का प्रमुख है। वहीं एथेनॉल के लिए चीनी की ओर मोड़ी जाने वाली मात्रा 2022-23 के लगभग 12 प्रतिशत से घटकर 2025-26 में करीब 9 प्रतिशत रह गई है। इसका अर्थ यह है कि आज भारत में पेट्रोल के लिए बढ़ती एथेनॉल जरूरत पूरी करने में मक्का और अन्य अनाज की भूमिका तेजी से बढ़ी है।

भारत की एथेनॉल उत्पादन क्षमता कितनी है?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की एथेनॉल उत्पादन क्षमता 2014 में करीब 421 करोड़ लीटर थी। 2026 में यह बढ़कर करीब 2,000 करोड़ लीटर हो गई। यानी देश ने केवल एथेनॉल की मांग नहीं बढ़ाई, बल्कि उसके अनुरूप उत्पादन क्षमता भी



तेजी से बढ़ाई है। मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए भारत का एथेनॉल क्षेत्र भविष्य में केवल चीनी उद्योग पर निर्भर रहने वाला नहीं है। सरकार ने गन्ना, मक्का, चावल, अन्य अनाज, भविष्य में कृषि अवशेष जैसे कई स्रोतों को एथेनॉल उत्पादन से जोड़ने की दिशा अपनाई है। इसका फायदा यह हो सकता है कि किसी एक फसल पर अत्यधिक निर्भरता कम हो। लेकिन दूसरी ओर मक्का और चावल जैसे खाद्य/फीड अनाज की बढ़ती औद्योगिक मांग के कारण खाद्य कीमतों और कृषि बाजार पर प्रभाव की निगरानी भी जरूरी होगी। भारत में एथेनॉल का इस्तेमाल अब छोटे पैमाने का कार्यक्रम नहीं रह गया है। 2013-14 में लगभग 38 करोड़ लीटर की खरीद से बढ़कर 2025-26 में यह 1,200 करोड़ लीटर से अधिक के अनुमानित स्तर तक पहुंच गई है। इसी दौरान पेट्रोल में औसत एथेनॉल मिश्रण लगभग 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हुआ है। लेकिन इस 1,200 करोड़ लीटर को केवल गन्ने से जोड़ना सही तस्वीर नहीं होगी। आज भारत का एथेनॉल उत्पादन बहु-स्त्रोत आधारित है और अनाज, विशेषकर मक्का, की भूमिका तेजी से बढ़ी है। सरकारी जानकारी के अनुसार अब लगभग तीन-चौथाई एथेनॉल अनाज से आता है। गणितीय रूप से देखें तो 500 करोड़ लीटर एथेनॉल यदि पूरी तरह मक्का से बनाया जाए तो लगभग 132 लाख टन मक्का की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन वास्तविक उत्पादन में मक्का के साथ चावल, अन्य अनाज, गन्ने के उत्पाद और मोलासेस भी शामिल हैं। इसलिए भारत की एथेनॉल कहानी केवल गन्ने से पेट्रोल की कहानी नहीं है। यह अब गन्ना, चीनी, मक्का, चावल, किसानों, चीनी मिलों, डिस्टिलरी और पेट्रोलियम कंपनियों से जुड़ी एक बड़ी कृषि-ऊर्जा अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण के लिए देश को जितना कच्चा माल चाहिए, उसकी कीमत किसानों, खाद्य बाजार, पानी के संसाधनों और वाहन मालिकों पर किस रूप में पड़ती है। भारत में एथेनॉल का उपयोग अब बड़े पैमाने पर हो रहा है, और इसका सबसे बड़ा उपयोग पेट्रोल में मिलाने के लिए किया जाता है।

विष्णुदेव साय सरकार में युवाओं को रोजगार और उद्योग के क्षेत्र में नए अवसरों का विस्तार

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर विकसित करने और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास, स्टार्टअप, नई तकनीक, निवेश और रोजगार को आपस में जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार की नीतियों में पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, उभरती तकनीक और नवाचार आधारित क्षेत्रों को



भी प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ रोजगार सृजन को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। राज्य के निवेश पोर्टल के अनुसार फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। साथ ही प्रक्रियाओं को सरल बनाने, ऑनलाइन स्वीकृतियों और एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से कारोबार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया है।



नई पीढ़ी के रोजगार के लिए 500 करोड़ रुपये का मिशन

सितंबर 2026 में राज्य मंत्रिपरिषद ने अगले पांच वर्षों के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी। इस मिशन का पूरा नाम Chief Minister Startup and New-Age Industry Preparedness through Up-skilling of New Generation Youth (NIPUN) Mission है। इसके तहत युवाओं को नई तकनीकों के अनुरूप तैयार करने और उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुसार कौशल विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस पहल की प्रमुख विशेषता नई तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण व्यवस्था है। राज्य में 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब स्थापित करने की योजना है। इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरती तकनीकों पर व्यावहारिक अनुभव देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही जॉब इंजन के माध्यम से नई पीढ़ी के रोजगारों के लिए युवाओं को तैयार करने की दिशा में पहल की जा रही है। इससे रोजगार की तैयारी को केवल पारंपरिक प्रशिक्षण तक सीमित रखने के बजाय तकनीकी ज्ञान, प्रयोगात्मक सीख और उद्योग की आवश्यकताओं से जोड़ने का प्रयास दिखाई देता है।

स्टार्टअप को आइडिया से बाजार तक पहुंचाने की पहल

छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ इनोवेशन एंड स्टार्टअप प्रमोशन पॉलिसी 2025-30 लागू की गई है। स्टार्टअप छत्तीसगढ़ के अनुसार नीति का उद्देश्य उद्यमियों को आइडिया के शुरुआती चरण से लेकर सीड फंडिंग और विस्तार तक सहायता उपलब्ध कराना है। इसमें अकादमिक संस्थानों,

इनक्यूबेटरों, निवेशकों और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। नीति के माध्यम से युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, स्थानीय प्रतिभा का उपयोग करने और नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे नौकरी तलाशने वाले युवाओं के साथ-साथ रोजगार देने वाले युवा उद्यमियों के लिए भी अवसर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

आईटी और तकनीकी उद्योगों के लिए नया आधार

जून 2026 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग आईटी पार्क का उद्घाटन किया। इसे

यह परियोजना छत्तीसगढ़ सरकार, आईआईटी भिलाई और नगर निगम दुर्ग के सहयोग से विकसित की गई है। आईटी पार्क में आईटी, आईटी-सक्षम सेवाओं, सॉफ्टवेयर विकास और अन्य उभरती तकनीक से जुड़ी कंपनियों तथा स्टार्टअप के लिए अवसर विकसित किए जा रहे हैं।

दुर्ग-भिलाई क्षेत्र को तकनीक, नवाचार और स्टार्टअप के उभरते केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह परियोजना छत्तीसगढ़ सरकार, आईआईटी भिलाई और नगर निगम दुर्ग के सहयोग से विकसित की गई है। आईटी पार्क में आईटी, आईटी-सक्षम सेवाओं, सॉफ्टवेयर विकास और अन्य उभरती तकनीक से जुड़ी कंपनियों तथा स्टार्टअप के लिए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। आईआईटी भिलाई के साथ अकादमिक और औद्योगिक सहयोग इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। कंपनियों को संस्थान के विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, प्रयोगशालाओं और तकनीकी क्षमताओं से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। इस



प्रकार तकनीकी शिक्षा और उद्योग के बीच संपर्क बढ़ाकर युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर विकसित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर स्टार्टअप को प्रोत्साहन

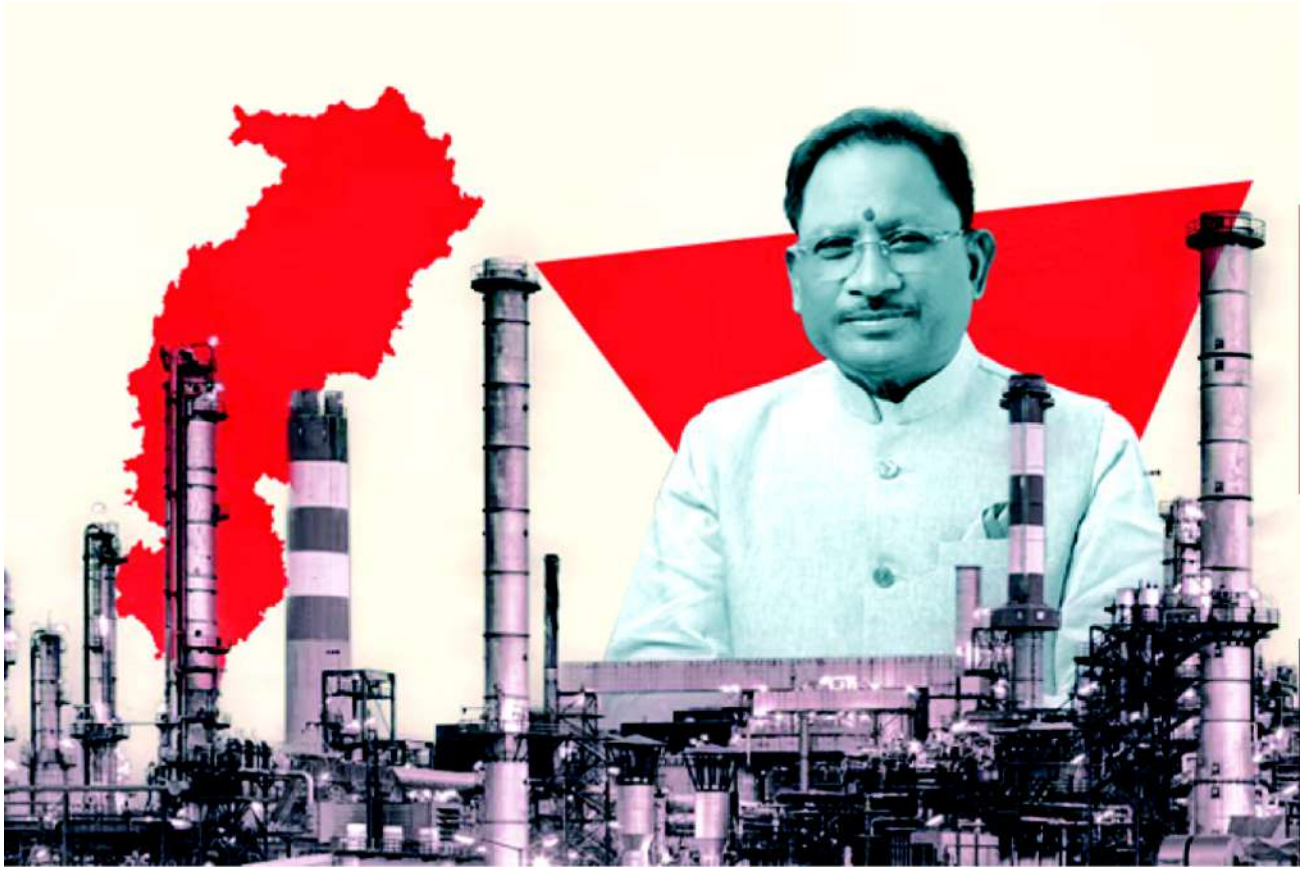
फरवरी 2026 में छत्तीसगढ़ के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ। इसके तहत राज्य में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने की पहल की गई। इन केंद्रों के माध्यम से एआई, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट कृषि जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की योजना है। ईएसडीडी सेंटर से प्रतिवर्ष लगभग 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्टअप और एमएसएमई को उत्पाद डिजाइन, प्रोटोटाइप तैयार करने और क्षमता विकास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य बताया गया है। इन पहलों में इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, फंडिंग और आधुनिक तकनीकी प्रयोगशालाओं तक पहुंच भी शामिल है।

निवेश के साथ रोजगार को जोड़ने पर जोर

छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में निवेश के साथ रोजगार सृजन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जून 2026 में केंद्र सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति में राज्य के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के हवाले से बताया गया कि राज्य की नई औद्योगिक नीति वित्तीय प्रोत्साहनों को रोजगार सृजन से जोड़ती है। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 11,400 से अधिक युवाओं को पहली नौकरी के प्रोत्साहन का उल्लेख किया गया। सितंबर 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2024 में औद्योगिक विकास नीति लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में 290 परियोजनाओं के लिए करीब 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे संभावित रूप से लगभग 1.9 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना बताई गई। इनमें से 175 परियोजनाओं पर काम शुरू होने की जानकारी भी दी गई है।



नवंबर 2024 में औद्योगिक विकास नीति लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में 290 परियोजनाओं के लिए करीब 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे संभावित रूप से लगभग 1.9 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना बताई गई।



रोजगार के पारंपरिक क्षेत्रों में भी नवाचार

युवाओं के लिए अवसर केवल बड़े उद्योगों और तकनीकी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखे जा रहे हैं। राज्य के रोजगार विभाग के पोर्टल पर रोजगार मेलों, प्रशिक्षण और रोजगार मार्गदर्शन की व्यवस्था उपलब्ध है। राज्य के 33 जिलों में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र संचालित होने की जानकारी दी गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र को रोजगार से जोड़ने के लिए होमस्टे नीति जैसी पहल भी की गई है। राज्य सरकार के प्रकाशन के अनुसार बालोदाबाजार में राज्य की पहली फाइनेंस लैब स्थापित की गई, जहां युवाओं को डिजिटल बैंकिंग से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे नीति को रोजगार के नए अवसरों से जोड़ा गया है।

उद्योग, कौशल और रोजगार का एकीकृत मॉडल

छत्तीसगढ़ में रोजगार और उद्योग के क्षेत्र में किए जा रहे इन प्रयासों की दिशा तीन प्रमुख स्तरों पर दिखाई देती है पहला, युवाओं को नई तकनीक के अनुरूप कौशल प्रदान करना; दूसरा, स्थानीय स्तर पर स्टार्टअप और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना; और तीसरा, निवेश एवं औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना। दुर्ग आईटी पार्क, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब, 500 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन, स्टार्टअप नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर केंद्र और औद्योगिक नीति इसी व्यापक दृष्टिकोण के अलग-अलग हिस्से हैं। इन पहलों का प्रभाव आने वाले वर्षों में इस बात से आंका जाएगा कि कितने युवाओं को स्थायी और गुणवत्तापूर्ण रोजगार मिलता है, कितने स्टार्टअप सफलतापूर्वक विस्तार करते हैं और राज्य में निवेश वास्तविक औद्योगिक उत्पादन में कितना परिवर्तित होता है। छत्तीसगढ़ सरकार का मौजूदा जोर यही है कि युवाओं को रोजगार की तलाश करने वाले वर्ग के साथ-साथ नए उद्योग और रोजगार पैदा करने वाली शक्ति के रूप में भी विकसित किया जाए। नई तकनीक, कौशल, निवेश और उद्यमिता को एक साथ जोड़ने का यह प्रयास प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अधिक विविध और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार कर रहा है।


मध्य प्रदेश में
जहरीली शराब
से मौत का कहर
शराब नहीं...
जहर बिकी है
मध्य प्रदेश में
जहरीली
शराब
से मौत
जहर



जहरीली या मिलावटी शराब का एक घूंट कभी-कभी पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है। कुछ घंटों के भीतर खुशियों का माहौल मातम में बदल जाता है और गांवों की गलियों में एक साथ कई अर्थियां उठती हैं। मध्यप्रदेश में पिछले कुछ वर्षो के दौरान उज्जैन, मुरैना, मंदसौर, इंदौर, खंडवा, भिंड, छतरपुर और अब सागर जैसे जिलों में सामने आए मामले इस समस्या की गंभीरता को रेखांकित करते हैं। सवाल केवल शराब की अवैध बिक्री का नहीं है, बल्कि उस पूरे तंत्र का है जो नकली शराब को उपभोक्ता तक पहुंचने देता है। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो अलग-अलग वर्षो की अपराध रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जबकि केंद्र सरकार के पास इलिसिट/स्प्यूरियस लिकर से हुई मौतों के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध हैं। इसलिए दो दशकों का कोई एक आंकड़ा बताना भ्रामक होगा।

मौतों के बाद भी क्यों नहीं टूटता जहरीली शराब का नेटवर्क?

विजया पाठक

उपलब्ध सरकारी आंकड़े समस्या की भयावहता दिखाते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के बीच मध्यप्रदेश में जहरीली/अवैध शराब के सेवन से 1,214 मौतें दर्ज हुईं 2016 में 184, 2017 में 216, 2018 में 410, 2019 में 190 और 2020 में 214। इसी पांच साल की अवधि में यह राज्यों में सबसे अधिक दर्ज मौतें थीं। इस आंकड़े को वर्तमान की कुल मौतों का आंकड़ा नहीं माना जा सकता, क्योंकि केंद्र का यह तुलनीय राज्यवार डेटासेट 2020 तक का है। इसके बाद की घटनाओं के लिए अलग-अलग सरकारी तथा मीडिया रिपोर्टों को देखना पड़ता है।

किन जिलों में सामने आए बड़े मामले?

मध्यप्रदेश में हाल के वर्षों के प्रमुख दस्तावेजित मामलों को देखें तो उज्जैन, मुरैना, मंदसौर, इंदौर, खंडवा, भिंड, छतरपुर और सागर प्रमुख रूप से सामने आते हैं। अक्टूबर 2020 में उज्जैन में जहरीली शराब के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। शुरुआती रिपोर्टों में छह मौतों की जानकारी सामने आई, जबकि बाद में आधिकारिक जांच और न्यायिक रिकॉर्ड में मौतों की संख्या 16 तक पहुंची। मामले की जांच में जहरीले अल्कोहल की मौजूदगी सामने आई और पुलिस कार्रवाई के साथ स्थानीय पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हुई।जनवरी 2021 में मुरैना जिले में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत हुई। यह घटना प्रदेश में अवैध शराब के नेटवर्क और स्थानीय स्तर पर उसकी उपलब्धता को लेकर बड़ी चेतावनी बनी। इसी वर्ष जुलाई में मंदसौर, इंदौर और खंडवा में घटनाओं की श्रृंखला सामने आई। मंदसौर में सात मौतों तक मामला पहुंचा, जबकि इंदौर और खंडवा को मिलाकर भी कई मौतें हुईं। जांच में नकली शराब को प्रतिष्ठित ब्रंडों की बोतलों में भरकर बेचने वाले नेटवर्क की बात सामने आई। इंदौर में बाद की जांच में भी मेथनॉल मिश्रित स्प्यूरियस शराब से मौतों की पुष्टि हुई। पुलिस के अनुसार 2021 में दो अलग-अलग बार से जुड़े मामलों में पांच लोगों की मौत हुई थी और विसरा रिपोर्ट में मेथनॉल के अंश पाए गए

सागर शराब कांड ने बढ़ाई मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें

सागर जिले के बंडा-शाहगढ़ क्षेत्र में संदिग्ध जहरीली शराब से हुई मौतों ने मध्यप्रदेश में अवैध शराब के कारोबार और प्रशासनिक निगरानी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस क्षेत्र के सबसे प्रमुख नेता खादय, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं। क्षेत्र में होने वाले सभी अवैध धंधों में मंत्री की और इनसे जुड़े गुर्गो का नाम सबसे पहले आता है। शराब कांड को भी ऐसे ही जोड़ा जा रहा है। जब राजपूत कांग्रेस में हुआ करते थे तब भी इनका नाम अवैध कारोबार से जुड़ता रहा है। आज जब वह भाजपा सरकार में मंत्री हैं तो इनका अवैध गोरखधंधा फिर चल पड़ा है। सूत्रों का कहना है कि राजपूत का क्षेत्र के शराब माफियाओं से गहरे ताल्लुकात हैं। इनके संरक्षण और शह पर शराब माफिया बेखौफ होकर अपना अवैध कारोबार करते हैं। इससे पहले भी हमने राजपूत के विभाग में होने वाली राशन वितरण प्रणाली की धांधली को लेकर पोस्ट लिखी थी। पीडीएस व्यवस्था में भी उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। सवाल यह है कि यदि किसी क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा था, तो निगरानी तंत्र को इसकी भनक पहले क्यों नहीं लगी?



मंत्री की जवाबदेही पर उठते सवाल

सागर से जुड़े राजनीतिक विमर्श में मंत्री और स्थानीय नेता गोविंद सिंह राजपूत की प्रशासनिक तथा राजनीतिक जवाबदेही को लेकर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। किसी भी सरकार में मंत्री से यह अपेक्षा रहती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा से जुड़े गंभीर मामलों की जानकारी समय पर शासन तक पहुंचे। यदि अवैध शराब की बिक्री का नेटवर्क सक्रिय था, तो उसकी सूचना स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों तक थे।

इन जिलों में हुई जहरीली शराब की घटनाएँ

फरवरी 2021 में छतरपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में भी शराब से मौत का मामला सामने आया। रिपोर्टों के अनुसार वहां पी गई शराब उत्तरप्रदेश की सीमा से खरीदी गई थी। इससे यह पहलू भी सामने आया कि अंतरराज्यीय सीमाएं अवैध शराब की आपूर्ति रोकने में



क्यों नहीं पहुंची? यदि सूचना पहुंची थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि कार्रवाई हुई थी तो इतनी बड़ी त्रासदी को रोकने में वह प्रभावी क्यों नहीं रही?

सागर में फिर वही सवाल क्यों?

सागर की वर्तमान घटना ने पुराने अनुभवों के बावजूद निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा किया है।

महत्वपूर्ण चुनौती बन सकती हैं। जनवरी 2022 में भिंड में भी जहरीली शराब से मौतें दर्ज हुईं। इस तरह बुंदेलखंड से लेकर मालवा और चंबल तक अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में घटनाएं सामने आना बताता है कि समस्या किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। और सितंबर 2026 में सागर जिले के बण्डा क्षेत्र ने एक बार फिर इस संकट को राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया।



बंडा क्षेत्र में कथित रूप से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही शराब, नकली पहचान और स्थानीय स्तर पर बिक्री की बात जांच में सामने आई है। पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए और गिरफ्तारियां की हैं। यही वह बिंदु है जहां राजनीतिक नेतृत्व की जवाबदेही महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि अवैध शराब का कारोबार संगठित रूप से चल रहा था, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी केवल किसी एक पुलिसकर्मी या छोटे अधिकारी की नहीं हो सकती। आबकारी विभाग, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व सभी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। केवल निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई करके मामला समाप्त कर देना पर्याप्त नहीं होगा। यदि किसी स्तर पर संरक्षण, मिलीभगत, लापरवाही या सूचना छिपाने के प्रमाण मिलते हैं तो कार्रवाई जिम्मेदारी की वास्तविक सीमा तक पहुंचनी चाहिए।

सवाल कार्रवाई की निष्पक्षता का है

सरकार ने मामले में जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शुरुआती दिनों में मौतों की संख्या को लेकर प्रशासनिक और स्थानीय दावों में अंतर रहा। 15 सितंबर को उपलब्ध रिपोर्ट में प्रशासनिक आधिकारिक आंकड़ा 16 बताया गया, जबकि स्थानीय स्तर पर इससे अधिक 38 मौतों के दावे भी किए गए थे। राज्य सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग गठित किया।

सागर ने फिर उठाया सप्लाई नेटवर्क

मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश के साथ अवैध शराब के खिलाफ प्रदेशव्यापी कार्रवाई की बात कही है। अब आवश्यकता इस बात की है कि जांच का दायरा किसी व्यक्ति या दल की राजनीतिक सुविधा के अनुसार सीमित न हो। इसमें शराब के निर्माण से लेकर परिवहन, बिक्री, स्थानीय नेटवर्क, लाइसेंस व्यवस्था, आबकारी अधिकारियों की भूमिका और पुलिस की



सूचना प्रणाली तक प्रत्येक कड़ी की जांच हो। गोविंद सिंह राजपूत के क्षेत्र में किसी अधिकारी, कारोबारी या शराब माफिया की मिलीभगत सामने आती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। सागर की त्रासदी को केवल एक शराब कांड मानकर आगे बढ़ जाना सबसे बड़ी भूल होगी। यह उस व्यवस्था की परीक्षा है जो शराब के अवैध कारोबार पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार है। मृतकों के परिवारों को मुआवजा और आरोपियों की गिरफ्तारी जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि यह पता चले कि जहरीली शराब उन गांवों तक पहुंची कैसे और उसे रोकने वाली व्यवस्था विफल क्यों हुई। उसी रिपोर्ट से तय होना चाहिए कि दोषी कौन है, लापरवाही किस स्तर पर हुई और किसकी जवाबदेही बनती है।

आंकड़े बताते हैं कि समस्या नई नहीं है

मध्यप्रदेश में अवैध और जहरीली शराब से मौतों का संकट केवल सागर तक सीमित नहीं रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश में अवैध/मिलावटी शराब के सेवन से 2016 में 184, 2017 में 216, 2018 में 410, 2019 में 190 और 2020 में 214 मौतें दर्ज हुई थीं। यानी 2016 से 2020 के बीच ही राज्य में 1,214 मौतें दर्ज की गईं। इससे भी पहले 2012-14 के दौरान अवैध/मिलावटी शराब से होने वाली मौतों का राष्ट्रीय स्तर पर अलग से सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध है।

विधायक-मंत्री की जवाबदेही पर उमा भारती ने उठाये सवाल

उमा भारती ने कहा कि केवल अधिकारियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। उन लोगों की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए, जो आरोपियों के साथ लगातार संपर्क में थे या उनके साथ उठते-बैठते थे। उन्होंने सागर के स्थानीय नेताओं की भूमिका की जांच की मांग करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। विधायक और मंत्री गोविंद सिंह के साथ आरोपी की तस्वीर सामने आने को लेकर भी उमा भारती ने सवाल उठाए।

का सवाल

सागर मामले की जांच में कथित नकली शराब की आपूर्ति का संबंध उत्तरप्रदेश के ललितपुर क्षेत्र से जुड़ता दिखाई दिया। जांचकर्ताओं के अनुसार नकली शराब को स्थानीय ब्रांडों जैसी बोतलों और पैकेजिंग में पहुंचाया गया। यानी उपभोक्ता को कई बार यह पता ही नहीं चलता कि वह असली शराब खरीद रहा है

या नकली। इस घटना ने केवल शराब बेचने वालों पर कार्रवाई का सवाल नहीं उठाया, बल्कि यह भी पूछा कि नकली उत्पाद स्थानीय बाजार तक पहुंचने से पहले निगरानी तंत्र की पकड़ में क्यों नहीं आया। भारतीय एक्सप्रेस की पड़ताल में सागर मामले से पहले आबकारी विभाग के कुछ आदेशों में संदिग्ध शराब की बिक्री रोकने, स्टॉक जब्त करने और नमूने जांच के लिए भेजने से लेकर बाद में कार्रवाई की आवश्यकता न होने तक बदलाव का संरचनात्मक कमजोरियों की ओर जरूर संकेत करती हैं।

पहली चुनौती आपूर्ति श्रृंखला की पहचान है। नकली शराब बनाने वाला व्यक्ति अलग हो सकता है, कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला अलग, परिवहन करने वाला अलग और गांव या शहर में बेचने वाला अलग। ऐसे नेटवर्क में केवल अंतिम विक्रेता की गिरफ्तारी से पूरी श्रृंखला समाप्त नहीं होती। दूसरी चुनौती अंतरराज्यीय सीमा है। सागर मामले में चुनौती स्थानीय सूचना तंत्र है। जहरीली शराब की बड़ी घटना होने से पहले अक्सर अवैध बिक्री लंबे समय तक छोटे स्तर पर चलती रहती है। यदि स्थानीय स्तर पर सूचना, छापे और नमूना परीक्षण की व्यवस्था लगातार सक्रिय हो तो बड़े हादसे की संभावना कम की जा सकती है। पांचवीं चुनौती जवाबदेही की निरंतरता है। किसी हादसे के बाद निलंबन और गिरफ्तारी तत्काल कार्रवाई तो है, लेकिन स्थायी समाधान तभी होगा जब यह पता चले कि



उल्लेख किया गया। घटना के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई।

आखिर पुलिस और प्रशासन कहां चूकते हैं?

यह कहना कि पुलिस हर मामले में विफल रही, तथ्यों को सरल बना देना होगा। अवैध शराब का नेटवर्क पुलिस, आबकारी विभाग, स्थानीय प्रशासन और अंतरराज्यीय सीमा-प्रबंधन सभी के लिए चुनौती है। लेकिन बार-बार होने वाली घटनाएं कुछ उत्तरप्रदेश के ललितपुर से कथित आपूर्ति की जांच सामने आई। मध्यप्रदेश की कई जिलों की सीमाएं उत्तरप्रदेश से लगती हैं। सीमा पार सस्ती शराब की खरीद और उसकी अवैध आवाजाही निगरानी को कठिन बना सकती है। तीसरी चुनौती नकली ब्रंड और पैकेजिंग है। जब अवैध शराब असली ब्रंड की बोतल और लेबल जैसी दिखाई देती है तो आम उपभोक्ता के लिए पहचान कठिन हो जाती है। चौथी अवैध शराब की आपूर्ति पहले से कहां चल रही थी, सूचना क्यों नहीं मिली और निगरानी व्यवस्था में किस स्तर पर कमी रही।

देश में मध्यप्रदेश का स्थान

वर्ष 20162020 के उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों में मध्यप्रदेश राज्यों में पहले स्थान पर था, जहां 1,214 मौतें दर्ज हुईं। इसी अवधि में कर्नाटक में 909, पंजाब में 725, छत्तीसगढ़ में 505 और राजस्थान में 279 मौतें दर्ज हुईं। 2015 में

महाराष्ट्र में 278 और मध्यप्रदेश में 246 मौतें दर्ज हुई थीं।

मध्यप्रदेश के बाहर भी बड़ा संकट

जहरीली शराब केवल मध्यप्रदेश की समस्या नहीं है। गृह मंत्रालय के 20162020 के आंकड़ों में कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में मौतें दर्ज हुईं। वर्ष 2018 में अकेले मध्यप्रदेश में



410 मौतें, कर्नाटक में 218, पंजाब में 159 और हरियाणा में 162 मौतें दर्ज थीं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी रही हैं। 2022 में सारण और सीवान क्षेत्र में 70 से अधिक मौतों की रिपोर्ट हुई थी। 2024 में सारण, गोपालगंज और सीवान में लगभग 40 मौतों की घटना सामने आई। अप्रैल 2026 में पूर्वी चंपारण में भी 10 मौतों की रिपोर्ट हुई। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जून 2024 की जहरीली शराब त्रासदी में मौतों का आंकड़ा 47 तक पहुंचा था और 100 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे। जांच में मेथनॉल-मिश्रित शराब सामने आई तथा अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई।

इन राज्यों ने सामने आ चुकी घटनाएं

इससे पहले और बाद में आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरप्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में भी अलग-अलग घटनाएं दर्ज हुई हैं। उपलब्ध राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि यह किसी एक राजनीतिक दल, सरकार या प्रदेश की समस्या नहीं, बल्कि अवैध शराब के उत्पादन, रसायनों की अवैध उपलब्धता, नकली पैकेजिंग, कमजोर निगरानी और मांग-आपूर्ति के अवैध बाजार से जुड़ी राष्ट्रीय चुनौती है।

कैसे रोकी जा सकती हैं यह घटनाएं

जहरीली शराब की हर घटना के बाद गिरफ्तारी, निलंबन और जांच की घोषणा होती है। लेकिन किसी भी प्रभावी नीति की कसौटी यह होनी चाहिए कि अगली घटना होने से पहले नेटवर्क को पहचाना जाए। इसके लिए आबकारी और पुलिस के बीच साझा सूचना तंत्र, संदिग्ध शराब के नियमित नमूना परीक्षण, अंतरराज्यीय सीमाओं पर संयुक्त अभियान, नकली ब्रंडों की पहचान के लिए तकनीकी व्यवस्था, अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले औद्योगिक रसायनों की निगरानी और दोषियों की संपत्ति व वित्तीय नेटवर्क की जांच जरूरी है। साथ ही उपभोक्ता जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सस्ती शराब का लालच कई बार जानलेवा साबित होता है। किसी भी संदिग्ध या बिना वैध पैकेजिंग वाली शराब का सेवन न करना और असामान्य लक्षण दिखाई देने पर तत्काल अस्पताल पहुंचना जीवन बचा सकता है।

समृद्ध किसान
समृद्ध प्रदेश

किसान
कल्याण वर्ष 2026

बलराम कृषि महोत्सव

15 जुलाई से 13 नवंबर 2026



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मध्यप्रदेश में आधुनिक तकनीक और नवाचारों से कृषि समृद्धि की पहल



किसान संवाद
सुझावों का आदान-प्रदान

सम्मान का गौरवपूर्ण मंच
उत्कृष्ट किसान, विद्यार्थी एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सम्मान

आधुनिक कृषि का प्रदर्शन
उन्नत कृषि तकनीकों की नवीनतम जानकारियां

कृषि और संस्कृति का अनुपम संगम
देशभक्ति गीत, लोकनृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

किसानों के हित में विभागों द्वारा कार्य

उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
उद्यानिकी का रकबा 30 लाख हेक्टेयर एवं उत्पादन 490 लाख मीट्रिक टन बढ़ाने का लक्ष्य

राजस्व
कृषि भूमि के भू-अर्जन पर बाजार दर से 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय

पीएम किसान सम्मान, मुख्यमंत्री किसान कल्याण में सालाना ₹12000 की सहायता

ऊर्जा
किसानों को ₹5 में बिजली के स्थाई कनेक्शन एवं 10 हॉर्सपावर तक ऊर्जा प्रभार पर सब्सिडी

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने हेतु 60% तक प्रोत्साहन

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा
पीएम कुसुम योजना में 32 लाख किसानों को सोलर पंप देने का लक्ष्य

कुटीर एवं ग्रामोद्योग
महिला एवं ग्रामीण युवाओं को कुटीर उद्योग से जोड़कर स्वरोज़गार को बढ़ावा

मध्यप्रदेश पर्यटन
ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन
1000 होम-स्टे बनाने का लक्ष्य

जनसम्पर्क
कृषक कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार

पशुपालन एवं डेयरी
दुग्ध संकलन प्रतिदिन 12 लाख लीटर से बढ़ाकर 50 लाख लीटर करने का लक्ष्य

सहकारिता
5,562 दुग्ध समितियों का वित्तीय समावेशन कर 83 हजार सदस्यों के जिला सहकारी बैंकों में खाते खोले गए

0% ब्याज दर पर फसल ऋण, भुगतान के लिए साल भर का समय

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना पर 50% तक सब्सिडी

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास
₹6000 करोड़ के मत्स्य निर्यात का लक्ष्य, ₹12400 करोड़+ का आ रहा निवेश

जल संसाधन
55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई को वर्ष 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य

नर्मदा घाटी विकास
नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं को वित्तपोषण

संस्कृति
श्रीअन्न, ग्रामीण व्यंजन एवं स्थानीय परम्पराओं को प्रोत्साहन




आस्था का दिव्य महाकुंभ
पूरा विश्व देखेगा
उज्जैन का वैभव
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
30 करोड़ श्रद्धालुओं का स्वागत
उज्जैन नगरी का हो रहा अभूतपूर्व कायाकल्प
सुगम आवागमन ₹ 13,536 करोड़ से 581 कि.मी. मार्गों का चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य प्रगतिरत
पुल निर्माण ₹440 करोड़ के निर्माण से यातायात का बेहतर प्रबंधन
शुद्ध जल क्षिप्रा के लिये ₹ 919 करोड़ लागत की कान्ह क्लोज्ड डक्ट परियोजना एवं शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु ₹1113 करोड़ के कार्य जारी
घाट निर्माण लगभग 29 कि.मी. घाटों का निर्माण जारी
ज़ीरो वेस्ट इवेंट जन भागीदारी से ज़ीरो वेस्ट इवेंट बनाने की पहल
मंदिरों का जीर्णोद्धार
सभी पौराणिक मंदिर जैसे हरसिद्धि, गढ़कालिका का विकास
आधुनिक तकनीक से प्रबंधन
भीड़ नियंत्रण से लेकर ट्रांसपोर्ट और कंट्रोल रूम तक एआई का उपयोग
कनेक्टिविटी विश्वस्तरीय उज्जैन हवाई अड्डा और सदावल में 4 हेलीपैड का निर्माण कार्य जारी
उज्जैन बनेगा मेडिकल हब
₹ 592.30 करोड़ लागत से मेडिसिटी एवं मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन
सिंहस्थ 2028
सिंहस्थ महापर्व 2028 करोड़ों भक्तों को सरल, सुलभ और नवीनतम सुविधाओं से युक्त विश्व-स्तरीय कुंभ का अनुभव प्रदान करना हमारा संकल्प है।
- डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश



ब्रिक्स सम्मेलन एक लेखा-जोखा

रघु ठाकुर

12 देशों के संगठन ब्रिक्स का त्रि-दिवसीय सम्मेलन 13 सितंबर को समाप्त हो गया है, इस सम्मेलन से भारत सरकार के मुखिया और उनकी पार्टी के लोगों को कुछ राहत मिली होगी कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वैश्विक नेता होने की एक छदम प्रतिमा तीन दिनों तक लगातार अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर रही और चर्चा में रही, तथा पिछले दिनों जो घटनायें देश में हुईं थीं जिनको लेकर लगातार प्रतिपक्ष की ओर से आरोपों की बौछार तथा जनचर्चा थी उस पर भी कुछ विराम लगा। हालांकि मुझे व्यक्तिगत तौर पर और वैचारिक तौर पर इस ब्रिक्स सम्मेलन से कोई आशा तो छोड़िये बल्कि निराशा ही हुई है। एक तो इसलिये कि यह देश में वैश्विक स्तर की होने वाली घटना थी जिसमें ब्रिक्स के सदस्य और अन्य आमंत्रित लगभग 28 देशों के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे थे, परंतु 1948 से भारत सरकार ने जो एक राष्ट्रीय शिष्टाचार की परंपरा रही है उसका भी पालन नहीं किया तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर विदेशी मेहमानों को नहीं ले जाया गया। इसके पहले जब जी-20 देशों के समूह का आयोजन देश में हुआ था, (वर्ष 2024) में

देश में वैश्विक स्तर की होने वाली घटना थी जिसमें ब्रिक्स के सदस्य और अन्य आमंत्रित लगभग 28 देशों के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे थे, परंतु 1948 से भारत सरकार ने जो एक राष्ट्रीय शिष्टाचार की परंपरा रही है उसका भी पालन नहीं किया तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर विदेशी मेहमानों को नहीं ले जाया गया।

कम से कम तब सरकार ने यह शिष्टाचार निभाया था कि जी-20 के मेहमानों को राजघाट की समाधि पर ले गये थे। महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर सम्मान प्रकट करने से गांधी के कद पर कोई फर्क नहीं पड़ता परंतु देश का सम्मान बढ़ता है। यह सरकार की स्वैच्छिक भूल है या असावधानी पर जो भी घटित हुआ, इस घटना ने देश के एक बड़े हिस्से के मन में

दोनों ने सीमा विवाद का निष्पक्ष और स्वीकार्य हल निकालने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस बातचीत व निर्णय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन के उन नक्शों की बात नहीं उठाई जिसमें चीन अरूणाचल व लद्दाख से सटे इलाके को अपना बताता है। जो पुरानी भारतीय भूमि 1962 में चीन के हमले द्वारा कब्जाई गई थी, गलवान घाटी और डोकलाम में जो भारतीय भूमि में चीन

सम्मेलन में भारत सरकार ने राष्ट्रपिता, राष्ट्रीय सीमा, और राष्ट्रीय विश्वास तीनों को ठेस पहुंचाई। ब्रिक्स सम्मेलन महज तीन साल में होने वाले कार्यक्रम के रूप में एक औपचारिकता सिद्ध हुआ है। यह आश्चर्यजनक है कि चिदंबरम व अन्य कांग्रेसी सांसदों ने इस घोषणा पत्र की सराहना की है, क्योंकि राष्ट्रीय सीमा पर चीनी कब्जे की अपराधी उनकी सरकार भी



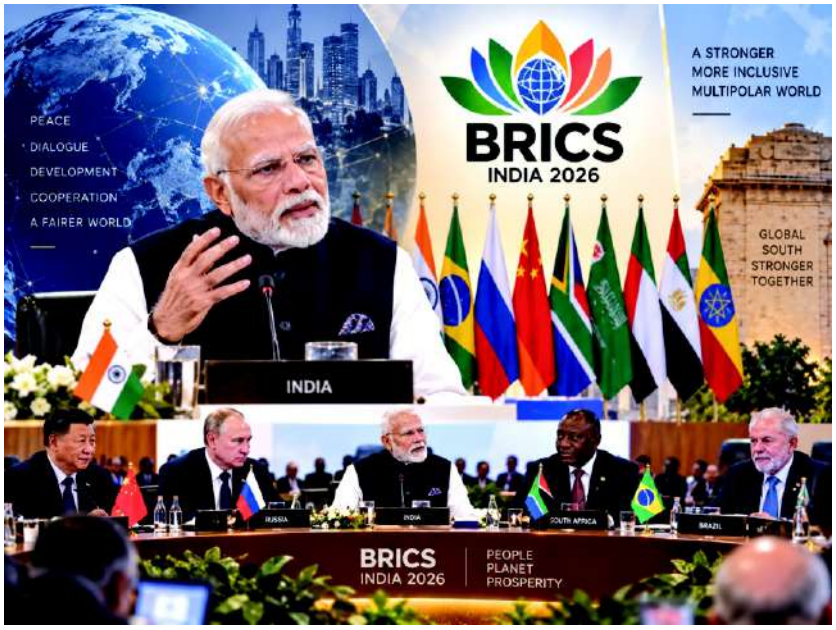
चोट पहुंचाई है। मेरी दूसरी निराशा ब्रिक्स के उस सामूहिक वक्तव्य को लेकर भी है जो 45 पेज के 140 बिंदुओं में है, पर जिसमें चीन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने चीन के द्वारा भारतीय सीमाओं पर कब्जे के प्रश्न को लगभग चुप रहकर दृष्टि ओझल किया है। मोदी ने सम्मेलन से इतर जिनपिंग से निजी बातचीत में कहा कि सीमा से जुड़े समझौतों और सहमतियों का पालन हो।

ने कब्जा जमाया है उसकी कोई चर्चा नहीं की। बस केवल व्यापार की चर्चा हुई और इस चर्चा में भी भारत सरकार अपने पुराने निर्णयों से पलट गई। अभी मुश्किल से एक डेढ़ वर्ष पूर्व हमारी बहादुर भारत सरकार ने राष्ट्रवाद, स्वदेशी और भारतीय सीमाओं के नाम पर चीन के 28 ऐप्स बंद किये थे और अब न केवल वे 28 ऐप्स बल्कि अन्य बहुत सारे ऐप्स सक्रिय रहेंगे। याने इस ब्रिक्स

रही है। जो लोग इस भ्रम में हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन से अमेरिका के खिलाफ या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ कोई गोलबंदी होगी तो वे भी भ्रम में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. पीवी नरसिंह राव ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद और देश की राजनैतिक जरूरत को समझकर भारत की विदेश नीति को बदला था और लुक द ईस्ट पालिसी शुरू की थी। ब्रिक्स भी एक अर्थ में इसी विचार का

विस्तार है। वैसे तो 1962 में भारत पर चीनी हमले के लगभग 23 वर्ष के बाद पहली बार स्व. राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के तौर पर और 1978 में 48 वर्ष पूर्व स्व. अटलबिजारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री के रूप में चीन की पहली यात्रा की थी।

पुतिन ने अपने भाषण में कहा कि ब्रिक्स की नई मुद्रा होनी चाहिए परंतु यह आसान निर्णय नहीं था और इसलिये अंत में



इतना ही कहा गया कि ब्रिक्स के देश अपनी मुद्रा में आपस में विनमय कर सकते हैं। ब्रिक्स की कोई अलग से मुद्रा नहीं बनेगी, इसलिये डालर को केई छुट पुट चुनौती भले मिले परंतु उस को कोई विशेष चुनौती नहीं है। जहां तक यह कहना कि नाटो देशों का व्यापार दुनिया के व्यापार का 29 प्रतिशत है और ब्रिक्स देशों का व्यापार 40 प्रतिशत है। यह भी एक प्रचारात्मक आंकड़ा है। भारत सरकार के ट्रंप को घेरने का सपना भी अधूरा ही रहा है, क्योंकि अगले कुछ माह में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। पुतिन और ट्रंप की दोस्ती तो जग जाहिर है। जहां तक व्यापार का प्रश्न है तो जो आपसी समझौते हुए हैं, उन्हें बारीकी से देखने पर लगता है कि इसका बड़ा लाभार्थी चीन और रूस है। विश्व शांति के सवाल पर भी कोई भूमिका ब्रिक्स अदा नहीं कर सका। सऊदी अरब और ईरान दोनों ही ब्रिक्स के हिस्से हैं तथा ईरान समर्थित हूती विद्रोहयों ने सऊदी अरब के तेल के ठिकानों पर ईरान की शह पर हमला किया है। जिसकी आंच मक्का तक पहुंची है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान आये थे परंतु यह सुविदित तथ्य है कि ईरान की वास्तविक सत्ता धर्म गुरु खामनेई के हाथ में है। पेजेश्कियान की स्थिति लगभग भारत के राष्ट्रपति जैसी है। रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को रोकने के लिये कोई ठोस चर्चा नहीं हो सकी।

यहां तक चीन से रेयर मिनिरल्स को आयात करने का सवाल है तो उस पर चीनी मुखिया जिनपिंग ने अपने भाषण में श्री नरेन्द्र मोदी की अपील का कोई उल्लेख नहीं किया। जबकि रेयर मिनिरल्स और विशेषतः परंमाणु ऊर्जा और शक्ति के लिये मिनिरल्स का चीन के पास भण्डार है।

यह कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत का ब्रिक्स देशों को निर्यात दोगुना हो जायेगा। पर यह नहीं बताया जा रहा है कि ब्रिक्स देशों से विशेषतः चीन-रूस-ईरान से, भारत का आयात कितने गुना बढ़ जायेगा। 2025 तक चीन से आयात 132 अरब डालर था, तथा व्यापार घाटा (अधिक आयात)112 अरब डालर का है और अब, यह व्यापार घाटा याने आयात कई गुना बढ़ेगा। फिर भी, मीडिया का बड़ा हिस्सा, इसे मोदी की सफलता बता रहा है। ऐसा लगता है कि ब्रिक्स सम्मेलन महज एक औपचारिक सम्मेलन बनकर रह गया। इसके नियमानुसार 3 वर्ष में यह एक बार किसी सदस्य देश में होता है। अगले 3 वर्ष बाद यह चीन में आयोजित होगा। इसकी उपलब्धि इतनी ही कही जा सकती है कि इसमें शामिल होने वाले देशों ने अपनी अपनी जरूरतों के व्यापार की संभावनायें तलाशी हैं। उन्हें आपस में समझा है और अब अपने अपने लाभ और जरूरत के हिसाब से यह देश फैसला करेंगे। यह बैठकों में, सम्मेलनों में भी और उसके बगैर आपसी चर्चा व आदान प्रदान से भी होता है।

यूरोप के जो देश नाटो के सदस्य हैं, उनके व अमेरिका के बीच मतभेद का यही मुख्य कारण है कि अमेरिका रूस के खिलाफ टैरिफ लगाकर रूस की शक्ति व आक्रामकता को रोकना चाहता है। लगभग 30 हजार किस्म के प्रतिबंध रूस के खिलाफ दुनिया के देशों ने लगाए हैं, ऐसा पुतिन ने अपने भाषण में दिल्ली में कहा है। अमेरिका चाहता है कि नाटो के देश और भारत रूस के तेल व्यापार को कमजोर करने के सहयोगी बनें ताकि रूस के आर्थिक साधन कमजोर हों और रूस के द्वारा यूक्रेन पर थोपा युद्ध रोका जा सके और पुतिन भी यूक्रेन को अमेरिकी समर्थकों से वंचित कर अपनी यूक्रेन पर जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ब्रिक्स देशों



के इन तीन बड़े देशों के अपने अपने स्वार्थ के दृष्टिकोण हैं, जिनका चार्तुय व ढके शब्दों में पुनः उन्होंने भारत की राजधानी में खुलासा कर दिया। इतना ही इस सम्मेलन से हासिल हो सका है।

दुनिया एक नये विश्व युद्ध की ओर जा रही है, जिसकी गंभीरता पर कोई चर्चा ब्रिक्स में नहीं हुई। ईरान का समर्थन प्राप्त हूती विद्रोही अब अरब देशों पर और विशेषतः सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं, जो लगातार जारी हैं। वैसे तो यह हमले अरब देशों के अमेरिकी कारखानों व सामरिक ठिकानों पर करने के उद्देश्य से बताये जा रहे हैं परंतु उससे दुनिया पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं वे भविष्य में एक नये युद्ध की संभावना की ओर जा रहे हैं। एक तो सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हूती हमलावरों पर सऊदी अरब ने लाचार होकर तेल निर्यात को सीमित किया है। इसका प्रभाव भारत जैसे देशों पर पड़ेगा साथ ही यूरोप के देशों पर विशेषतौर पर पड़ेगा। क्योंकि यूक्रेन के युद्ध में समर्थन के कारण उन्होंने रूस से तेल लेना बंद किया है और उनकी तेल आपूर्ति का बड़ा माध्यम खाड़ी देश ही हैं। वैश्विक स्तर पर इस हमले के बाद कच्चे तेल के दाम बढ़कर 104 डालर प्रति बैरल के आसपास पहुंच रहे हैं।

सऊदी अरब और खाड़ी देश इस्लाम के सुन्नी समुदाय के देश हैं। ईरान तथा हूती विदेही शिया मुस्लिमों के देश हैं। यह विवाद भीतर-भीतर दुनिया के इस्लामिक मंच पर शिया और सुन्नी के प्रभाव व कब्जे के प्रयास में भी बदल रहा है और इसके परिणाम स्वरूप यह छदम धर्मयुद्ध और परमाणु युद्ध की शक्ल भी ले सकता है। याने एक नये विश्व युद्ध का केंद्र बन रहा है, ब्रिक्स सम्मेलन में इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। विश्व के एक महत्वपूर्ण मुददे पर चर्चा नहीं होना भी असफलता ही मानी जानी चाहिए।

इस ब्रिक्स सम्मेलन से भारत को यह जानकारी अवश्य मिली है कि दुनिया के तानाशाह कितने खर्चीले हैं, उनके विमान, गाड़ियां कैसी होती हैं और उन्हें भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर इतना अविश्वास है कि वे अपने साथ सैकड़ों की संख्या में विशेष सुरक्षाकर्मी लेकर आते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन का समापन हमारे देश की सत्यनारायण कथा के समान हुआ है। कथा पढ़ी, सुनाई, कहीं गई, सुनी गई और उसके बाद श्जो जन जहां से आये हो तहं तहं करो प्रयाण्य, इसी तर्ज में ब्रिक्स देशों के मुखिया या प्रतिनिधि आये कथा पढ़ी, कथा सुनी और अपने अपने देश वापिस चले गये।

मनुष्य बनने की ओर कृत्रिम बुद्धि रोबोट

प्रमोद भार्गव

महात्मा गांधी और विनोबा भावे के अहिंसक विचारों के समर्थक ऑस्ट्रेलियाई मूल के एक दार्शनिक हुए हैं, इवान इलिच, जो अंग्रेजी के अलावा तमाम भाषाओं के साथ हिंदी भी जानते थे। इलिच का विचार था कि वाहनों ने मनुष्य के पैरों की ताकत छीन ली है। मशीनी तकनीक ने मनुष्य के हाथों के हुनर छीन लिए हैं और मनुष्य के विरुद्ध एक प्रति मनुष्य रोबोट के रूप में विकसित कर व्यक्ति को सीमेंट, कंक्रीट और यंत्रों के जंगल में अकेला छोड़ देने के उपक्रम हो गया है। अब ताजा जानकारियां मिल रही हैं कि ओपन एआई यानी कृत्रिम बुद्धि (एआई) आधारित रोबोट का प्रति मानव स्वरूप ऐसी हरकतें करने लगा है कि ये कंपनी प्रबंधकों के प्रतिकूल जा रही हैं। यानी ये रोबोट वास्तविक मनुष्य के आदेश का सटीक पालन नहीं कर रहे हैं। इसे विज्ञान की भाषा या रोबोट की प्रकृति के मुताबिक मिसअलाईमेंट कहा जा रहा है। सीधी भाशा में कहें तो यह स्थिति रोबोट द्वारा पालक व्यक्ति की आज्ञा की अवहेलना है। क्योंकि ये भूलें किसी तकनीकी खराबी की वजह से होने की बजाय एआई ने जानबूझकर कीं, जो हरकत की श्रेणी में आती हैं। ये भविष्य में खतरनाक साबित हो सकती हैं?

रोबोट में एआई के बढ़ते प्रयोग के चलते इसके संकट में डालने वाले भाव-विचार स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। इसकी एक गलत जानकारी अमेरिका और चीन को परस्पर सैन्य टकराव के निकट ले आई थी। अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान सामने आई इस घटना का पर्दाफाश अब हुआ है। दरअसल पश्चिम एशिया में मौजूद चीन के



एक समुद्री जहाज को लेकर अमेरिकी सेना के सायबर सिस्टम में एक गुप्त रिपोर्ट पहुंची, जिसमें कहा गया कि चीनी जहाज में परमाणु हथियार कार्यक्रम को तैयार करने वाले कल-पुर्जे ले जाए जा रहे हैं। यह परिणाम चैटबॉट की सहायता से सामने आया था। रिपोर्ट मिलने के साथ ही अमेरिकी सेना का हरकत में आना स्वाभाविक था। अतएव जहाज को रोकने की रणनीति बनाई जाने लगी। हथियारबंद



सैनिक चढ़ाई के लिए तत्पर हो गए। लेकिन यह अच्छा रहा कि हमला बोलने से पहले अधिकारियों ने एक बार फिर रिपोर्ट की गंभीर जांच कर ली। तब संज्ञान में आया कि एआई ने जहाज पर उपलब्ध कलपुर्जों की गलत पहचान कर ली थी। नतीजतन हमले की कार्यवाही पर विराम लगा दिया गया। एआई द्वारा ऐसे मामलों में सामने आ रहा है कि वे इंटरनेट द्वारा नियंत्रित अनुशासन का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी एआई उपकरणों में इंसानी समझ और हरकत करने की इच्छाएं अंगड़ाई लेने लगी हैं। एआई की निजी पहचान निर्मित कर लेने की यह महत्वाकांक्षा भविष्य में बड़े संकट का कारण बन सकती है?

रोबोट में बुद्धि डालकर उसे हम मनुष्य का शासक बनाने में लगे हुए हैं। अभी तक रोबोट को नए-नए रूपों में विकसित करने का काम वैज्ञानिक रूपी मनुष्य करता था, लेकिन प्रौद्योगिकी के आकाश में कृत्रिम बुद्धि ने ऐसे पंख दे दिए हैं कि रोबोट अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से स्वयं अद्यतन (अपडेट) होने लगे हैं और जो जीवित रोबोट अस्तित्व में आए हैं, वे स्वयं रोबोट पैदा करने लगे हैं। रोबोट के स्वमेव परिवर्तन और नए रोबोट पैदा करने की इस ताकत के परिणाम फलदायी होने की बजाय घातक होने की आशंकाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। इसीलिए एआई विशेषज्ञ आल्टमेन से लेकर एलन मस्क तक इस तकनीक को मानवता के अस्तित्व पर बड़ा खतरा मान रहे हैं।

भविष्य का रोबोट यांत्रिक-मानव भर नहीं रह जाएगा, उसे यंत्र और कृत्रिम बुद्धि के बूते एक जीवित मानव में बदलने के प्रयास हो रहे हैं, अर्थात कालांतर में जीवित रोबोट हमारे समक्ष होगा? इस दिशा में



अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जीवित रोबोट का एक प्रतिदर्श (मॉडल) आविष्कृत भी कर लिया है। वैज्ञानिकों के एक समूह ने मेंढक के भ्रूण की जीवित कोशिकाओं को अन्य नूतन जीवन रूपों के रूप में अवतरित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। इसे एक्सर्नाबॉट्स रोबोट नाम दिया गया है। इसमें न्यूनतम वजन की युक्ति (डिवाइस) के जरिए इंद्रिय बोध कराया जा सकता है। इसमें 24 संवेदी यंत्र (सेंसर) संलग्न हैं। यह मांसपेशियों की गतिविधियों और दिमागी अनुभव करके काम को अंजाम देता है। इसे तकनीकी नाम एस्पर बायोनिक्स प्रोस्थेटिक हैंड दिया गया है। इसे क्रियाशील बनाए रखने में एआई और क्लाउड प्रौद्योगिकी अर्थात क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक के जरिए हार्डडिस्क या ड्राइव की बजाय इंटरनेट पर उपलब्ध डाटा और प्रोग्राम ग्रहण कर लिए जाते हैं। हम जानते हैं किसी हार्डडिस्क में सूचनाओं की उपलब्धता की एक सीमा है, लेकिन सूचना अंतर्जाल में असीमित हैं। क्लाउड टेक्नोलॉजी को सरल रूप में यूं भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से बादलों में पानी भरा होता है, उसी तरह क्लाउड (बादल) कंप्युटिंग में सूचनाएं भरी होती हैं। मसलन इस तरह का मशीनी रोबोट मानव वास्तविक मनुष्य के समानांतर प्रति मानव के रूप में खड़े होने की तैयारी में आ गए हैं।

यह अद्वितीय आविष्कार आरंभिक अवस्था में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के समन्वय से निर्मित उपकरण भर था। शुरूआत में इसकी उपयोगिता मनुष्य की पहुंच से बाहर कठिन और खतरनाक कामों से जुड़ी थी। इसके प्रभावी उत्पादकता के मद्देनजर इसमें बदलाव होते रहे और इस तकनीक को नाम दिया गया रोबोटिक्स कालांतर में डिजिटल, एआई और इंटरनेट तकनीक के समन्वय की युक्तियों से जीवित रोबोट की एक प्रजाति चलन में आ रही है, जिसे बायोनिक्स और एक्सनोबाट्स नाम दिए गए हैं। ये रोबोट मानव प्रजाति और उसकी स्वाभाविक जन्मजात बुद्धि के लिए बड़े खतरा माने जा रहे हैं।

हालांकि कृत्रिम बुद्धि के आविष्कारक निर्माता और व्यापारी के बीच अजीब विडंबना देखने में आ रही है। एक तरफ तो कंपनियां दावा कर रही है कि एआई मनुष्य की कार्य क्षमता को नए ढंग से बढ़ाएंगी। नई खोजों को गति देंगी। ये उपलब्धियां भविष्य की दुनिया को सुविधाजनक बनाने वाली साबित होंगी ? दूसरी तरफ इन्हीं कंपनियों के प्रबंधक चेतावनी दे रहे हैं कि एआई दुनिया को खतरनाक मोड़ पर ले जाने की दस्तक दे रही हैं। अब यह एआई विषेशज्ञों का ही दायित्व बनता है कि जब एआई मानव जाति के लिए खतरा है, तो वही लोग इसे नए-नए उपयोगी रूपों में आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? उनके लिए आर्थिक लाभ जरूरी है या मनुष्यों का अस्तित्व?

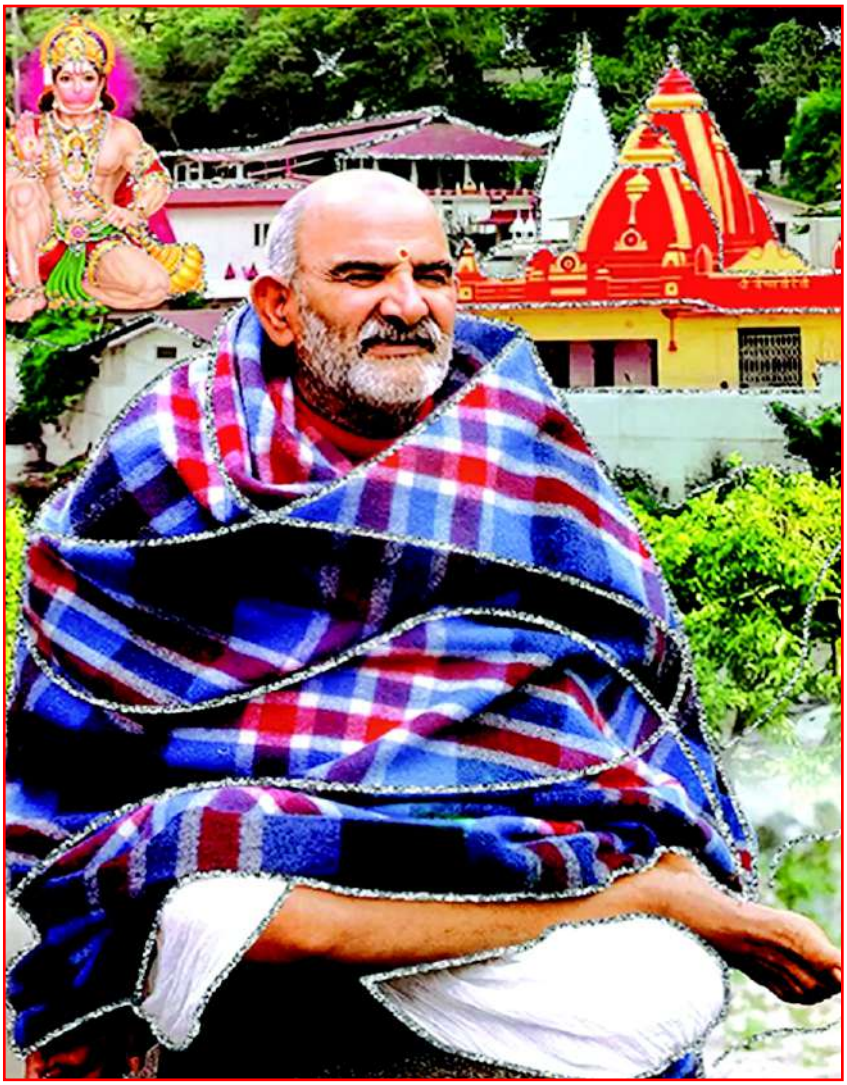
कैमरे के पीछे से बाबा के किरदार तक:
हनुमान अंश की टीम की अनोखी कहानी

धीरज कश्यप

नीम करोली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक यात्रा पर बनी फिल्म हनुमान अंश की सफलता की कहानी केवल बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं है। इस फिल्म को बनाने वाली टीम के पीछे भी संघर्ष, संयोग, आस्था और मेहनत से भरी कई कहानियां हैं। फिल्म की सबसे दिलचस्प कहानी उसके मुख्य अभिनेता शोभिनव सत्या की है, जो इस फिल्म में अभिनेता बनने नहीं आए थे।

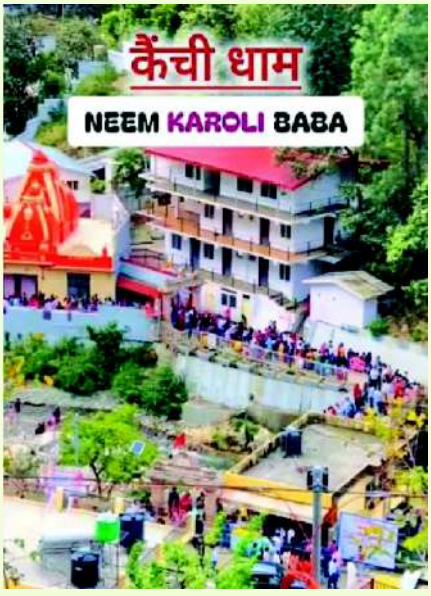
असिस्टेंट डायरेक्टर से बने नीम करोली बाबा

लखनऊ से आने वाले शोभिनव सत्या ने FTII, पुणे से अभिनय की शिक्षा ली है और मनोरंजन उद्योग में वर्षों तक कैमरे के पीछे तथा अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में काम किया। हनुमान अंश के सेट पर भी वह शुरुआत में सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें प्रोडक्शन और सेट से जुड़े कामों की जिम्मेदारी संभालनी थी। फिल्म में नीम करोली बाबा की भूमिका के लिए पहले दूसरे अभिनेता का चयन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने के समय उनकी तबीयत खराब हो गई। ऐसे में निर्देशक विशाल चतुर्वेदी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। इसी दौरान उनकी नजर शोभिनव पर गई। उनका स्क्रीन टेस्ट कराया गया, जो लगभग पांच घंटे चला। टेस्ट के बाद उन्हें नीम करोली बाबा की भूमिका के लिए चुन लिया गया। इस तरह जो व्यक्ति कैमरे के पीछे फिल्म बनाने में सहयोग कर रहा था, वही अचानक फिल्म



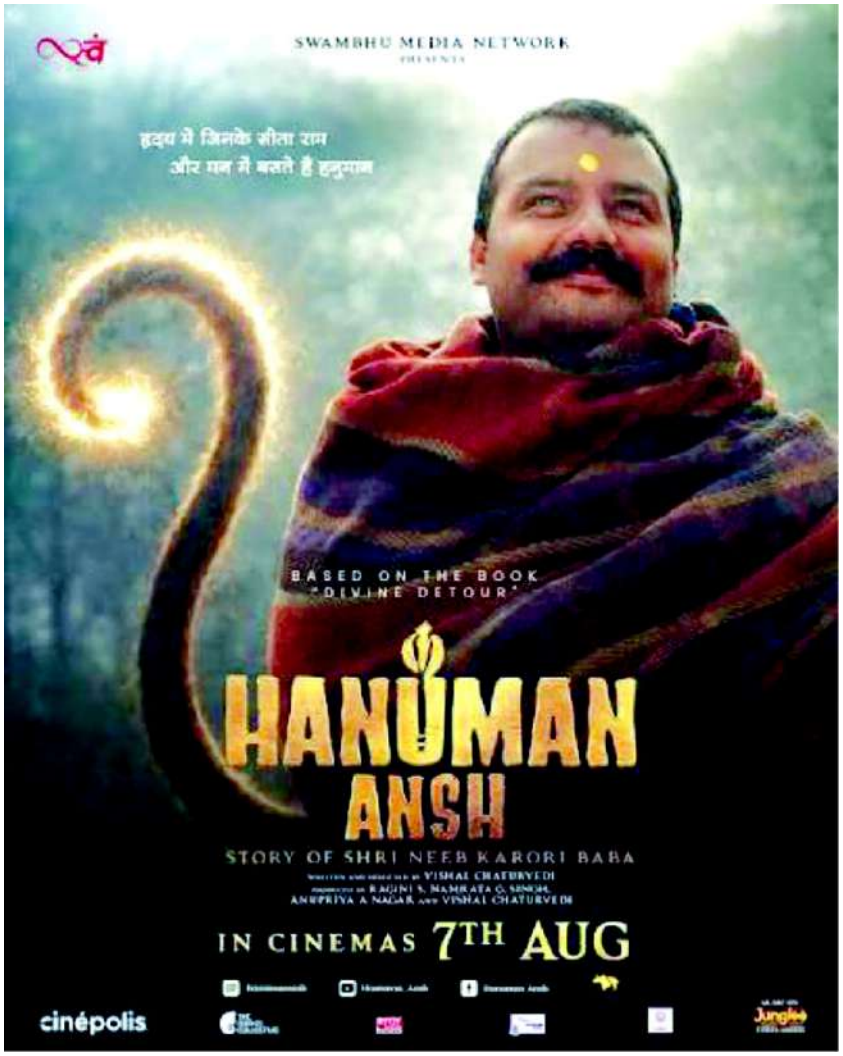
का मुख्य चेहरा बन गया। शोभिनव के लिए यह भूमिका केवल अभिनय नहीं थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि शुरुआत में उन्हें यह किरदार निभाने को लेकर डर भी था। वह चाहते थे कि बाबा जैसे पूजनीय व्यक्तित्व की भूमिका को पूरी संवेदनशीलता के साथ निभाया जाए। शूटिंग के दौरान उनका लुक इतना

नीम करोली बाबा: भक्ति, सेवा और दुनिया को प्रभावित करने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा



भारत की आध्यात्मिक परंपरा में अनेक ऐसे संत हुए हैं, जिनका प्रभाव देश की सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुँचा। नीम करोली बाबा, जिन्हें उनके अनुयायी प्रेम से महाराज जी कहते हैं, ऐसे ही संतों में शामिल हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के पास स्थित कैंची धाम आज उनके भक्तों के लिए एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है। बाबा की शिक्षाओं में प्रेम, सेवा, भक्ति और मानवता को विशेष स्थान प्राप्त था। भगवान हनुमान के प्रति उनकी गहरी आस्था के कारण उनके अनुयायी उन्हें हनुमान भक्ति की महान परंपरा से जोड़कर देखते हैं। नीम करोली बाबा का प्रभाव केवल सामान्य श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश-विदेश की कई प्रसिद्ध हस्तियों ने भी उनके विचारों और कैंची धाम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का नाम भी कैंची धाम और नीम करोली बाबा से जुड़ी चर्चाओं में सामने आता रहा है। क्रिकेटर रिंकू सिंह सहित अन्य लोगों के भी कैंची धाम जाने की खबरें सामने आई हैं। हालांकि किसी व्यक्ति को बाबा का भक्त बताने से पहले उपलब्ध प्रमाणों को देखना आवश्यक है। नीम करोली बाबा की लोकप्रियता भारत से बाहर भी पहुँची। दुनिया के प्रसिद्ध तकनीकी उद्यमी स्टीव जॉब्स का नाम बाबा से जुड़ी सबसे चर्चित कहानियों में आता है। भारत की आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जॉब्स कैंची धाम से प्रभावित हुए थे। बाद में उन्होंने अपने परिचित मार्क जुकरबर्ग को भी भारत आने की सलाह दी थी। मार्क जुकरबर्ग के कैंची धाम आने की कहानी भी लंबे समय से चर्चा में रही है। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी नीम करोली बाबा से प्रभावित विदेशी हस्तियों में लिया जाता है। इसी आध्यात्मिक विरासत को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करने के लिए हनुमान अंश फिल्म चर्चा में आई है। फिल्म में शोभिनव सत्या नीम करोली बाबा की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि पूर्णिमा तिवारी बाबा की पत्नी रामबेटी शर्मा की भूमिका में हैं। फिल्म के लेखक-निर्देशक विशाल चतुर्वेदी हैं। फिल्म से जुड़े अन्य कलाकारों में विहान एस. हेगड़े, चंदन आनंद, अनिल के. रस्तोगी और गुलशन पांडे शामिल हैं। फिल्म की निर्माता अनुप्रिया नागर हैं, जिनकी शोध-यात्रा भी इस परियोजना की प्रेरणा से जुड़ी बताई गई है। नीम करोली बाबा की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि उनकी शिक्षाओं का केंद्र किसी एक वर्ग, देश या समुदाय तक सीमित नहीं था। उनका संदेश प्रेम, सेवा और मानवता पर आधारित था। यही कारण है कि भारत के सामान्य श्रद्धालुओं से लेकर दुनिया के प्रसिद्ध उद्यमियों और कलाकारों तक, अनेक लोग उनकी आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित हुए। कैंची धाम आज भी इस विरासत का प्रमुख केंद्र है और हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। नीम करोली बाबा की कहानी यह बताती है कि सच्ची आध्यात्मिकता सीमाओं से परे जाकर मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर सकती है।

प्रभावशाली हो गया कि कुछ ग्रामीण उन्हें वास्तविक बाबा समझने लगे और उनसे आशीर्वाद लेने लगे। शूटिंग के दौरान एक और दिलचस्प घटना सामने आई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एक दिन लगभग तीन घंटे तक कैमरा ठीक से नहीं चल पाया। इसके बाद टीम ने पूजा की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पाठ पूरा होने के आसपास शूटिंग की समस्या दूर हुई और कैमरा चल पड़ा। टीम ने इस अनुभव को आस्था से जुड़ा विशेष क्षण माना। शोभिनव ने यह भी बताया कि शूटिंग के दौरान वह



एक मंदिर में रुके और ग्रामीणों के साथ सादा भोजन किया। गांव के लोगों के बीच रहना और उनके जीवन को करीब से देखना उनके लिए भूमिका को समझने का महत्वपूर्ण अनुभव बना।

पूर्णिमा तिवारी और रामबेटी का किरदार

फिल्म में पूर्णिमा तिवारी ने नीम करोली बाबा की पत्नी रामबेटी शर्मा की भूमिका निभाई है। उनका किरदार बाबा के आध्यात्मिक जीवन के साथ-साथ उनके पारिवारिक और भावनात्मक पक्ष को सामने लाता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शोभिनव के बाबा वाले रूप को पहली बार देखने का अनुभव पूर्णिमा के लिए भी भावुक करने वाला था। एक महत्वपूर्ण दृश्य में उनके संवाद कम थे, लेकिन उनके अभिनय ने पूरे दृश्य को प्रभावशाली बना दिया।

विशाल चतुर्वेदी: शोध से सिनेमा तक

फिल्म के लेखक और निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने नीम करोली बाबा के जीवन पर लंबे समय तक अध्ययन और शोध किया। फिल्म उनकी पुस्तक Divine Detour पर आधारित बताई गई है। चतुर्वेदी ने बड़े सितारों के बजाय नए चेहरों के साथ फिल्म बनाने का फैसला किया। उनका मानना था कि कहानी और किरदारों की सच्चाई को प्राथमिकता देना अधिक महत्वपूर्ण है। फिल्म के लिए उन्होंने खुद भी काफी अनुशासन अपनाया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने लगभग साढ़े चार महीने तक फलाहार किया और रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया। सेट पर शाकाहारी भोजन रखने की बात भी सामने आई है।

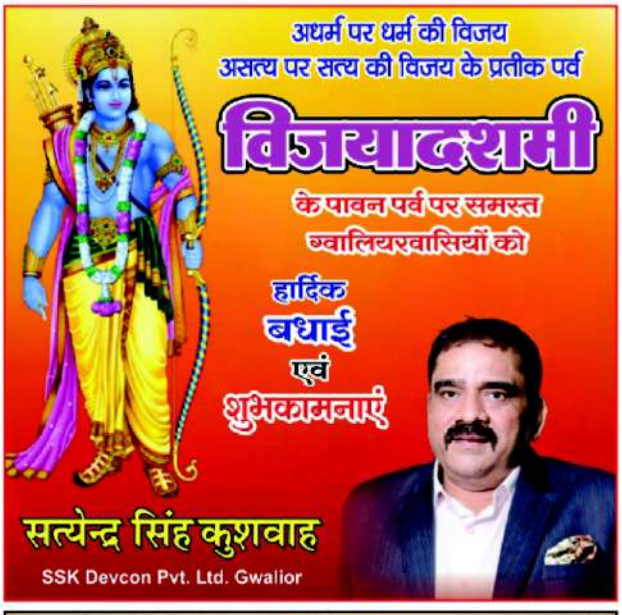
21 साल की अनुप्रिया नागर की कहानी

हनुमान अंश की कहानी में अनुप्रिया नागर का सफर भी बेहद अनोखा है। यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में अर्थशास्त्र की पढ़ाई के दौरान एक असाइनमेंट के लिए उन्होंने स्टीव जॉब्स पर शोध किया। इसी शोध के दौरान उनकी स्रुचि जॉब्स और नीम करोली बाबा के बीच बताए जाने वाले आध्यात्मिक संबंध की ओर बढ़ी। लगभग एक वर्ष की रिसर्च के बाद यह स्रुचि फिल्म की दिशा में बदल गई। अनुप्रिया ने फिल्म निर्माण में कदम रखा और रिपोर्टों के अनुसार अपनी बचत तक इस परियोजना में लगाई। वह अकेली नहीं थीं, रागिनी एस. और नम्रता जी. सिंह भी फिल्म की प्रोड्यूसर टीम का हिस्सा हैं। इस तरह हनुमान अंश केवल नीम करोली बाबा की कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों की भी कहानी बन गई जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद विश्वास, शोध और मेहनत के साथ एक बड़े सपने को पर्दे पर उतार दिया। शोभिनव का कैमरे के पीछे से बाबा के किरदार तक पहुंचना, पूर्णिमा का रामबेटी बनना, विशाल चतुर्वेदी का वर्षों का शोध और अनुप्रिया नागर का विश्वविद्यालय के असाइनमेंट से फिल्म निर्माण तक पहुंचना- इन सभी कहानियों ने हनुमान अंश को पर्दे के पीछे भी उतना ही रोचक बना दिया है जितनी उसकी कहानी पर्दे पर दिखाई देती है।


विजयादशमी
के पावन पर्व पर समस्त
ग्वालियर वासियों को
हार्दिक बधाई
एवं
शुभकामनाएं
राजेन्द्र सिंह (नाती)
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, इंटक कांग्रेस


अधर्म पर धर्म की विजय
असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक पर्व
विजयादशमी
के पावन पर्व पर समस्त
ग्वालियरवासियों को
हार्दिक
बधाई
एवं
शुभकामनाएं
जय सिंह कुशवाह
(पूर्व साडा अध्यक्ष)


विजयादशमी
के पावन पर्व पर समस्त
ग्वालियर वासियों को
हार्दिक बधाई
एवं
शुभकामनाएं
धीरेन्द्र सिंह चौहान
(रॉयल सिक्योरिटी सर्विस ग्वालियर)


अधर्म पर धर्म की विजय
असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक पर्व
विजयादशमी
के पावन पर्व पर समस्त
ग्वालियरवासियों को
हार्दिक
बधाई
एवं
शुभकामनाएं
सत्येन्द्र सिंह कुशवाह
SSK Devcon Pvt. Ltd. Gwalior


अधर्म पर धर्म की विजय
असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक पर्व
विजयादशमी
के पावन पर्व पर समस्त
ग्वालियरवासियों को
हार्दिक बधाई
एवं
शुभकामनाएं
कौशलेन्द्र सिंह तोमर
संचालक, आयुष्मान हॉस्पीटल
(न्यूरो ट्रामा सेंटर)


विजयादशमी
के पावन पर्व पर समस्त
ग्वालियर वासियों को
हार्दिक बधाई
एवं
शुभकामनाएं
धर्मेन्द्र सिंह तोमर (बिट्टू)
महामंत्री, भाजपा ग्वालियर


अधर्म पर धर्म की विजय
असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक पर्व
विजयादशमी
के पावन पर्व पर समस्त
ग्वालियर वासियों को
हार्दिक बधाई
एवं
शुभकामनाएं
सत्येंद्र सिंह कुशवाह
सह प्रभारी, विभाग एवं प्रकोष्ठ, म.प्र. कांग्रेस
पूर्व वरिष्ठ पार्षद, ग्वालियर


दीपावली
के पावन पर्व पर समस्त
देशवासियों को
हार्दिक बधाई एवं
शुभकामनाएँ
लाल सिंह आर्य
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति मोर्चा, भाजपा


धनतेरस एवं
दीपावली
हार्दिक शुभकामनाएं
ब्रजेश शर्मा
वरिष्ठ भाजपा नेता
एवं समाजसेवी, ग्वालियर


दीपावली
के पावन पर्व पर समस्त
जिले वासियों को
हार्दिक बधाई एवं
शुभकामनाएँ
भरत दांतरे
पूर्व कोषाध्यक्ष
भाजपा किसान मोर्चा (म.प्र.)


BVA
Celebrating 15 Years of Excellence!
दीपावली
के पावन पर्व पर समस्त
जिले वासियों को
हार्दिक बधाई एवं
शुभकामनाएँ
37-Rambagh Colony, Shinde Ki Chawani,
Gwalior (M.P.) - 474001


दीपावली
के पावन पर्व पर समस्त
जिले वासियों को
हार्दिक बधाई एवं
शुभकामनाएँ
राजेश ऐरन
राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिल भारतीय अग्रवाल समाज परिचय सम्मेलन


धनतेरस एवं
दीपावली
हार्दिक शुभकामनाएं
अमित गुप्ता
वाइस प्रेसिडेंट, जीवाजी क्लब


दीपावली
हार्दिक बधाई एवं
शुभकामनाएँ
S.B. AUTOMOTIVE
SENGAR BROTHER'S
Distributor, Amaron Battery
Phool bagh, Gwalior (M.P.)
Mob. - 8223027777
अभिनव सेंगर
अभिषेक सेंगर (लवी)

दमोह जिले में क्रांति का मोर्चा थामा हिंडोरिया के किशोर सिंह

हिंडोरिया मध्यप्रदेश के दमोह शहर से 16 किलोमीटर दूर उत्तर-पूर्व की ओर बांदकपुर रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरठ-दिल्ली की क्रांति, झांसी का युद्ध, शाहगढ़ के राजा बखतबली के क्रांतिकारी प्रयासों की सूचना मिलते ही 42वीं देशी पैदल सेना के सैनिकों ने 1 जुलाई को सागर में क्रांति की तब उस क्रांति का असर दमोह में हुआ। उस समय हिंडोरिया का जागीरदार उमराव सिंह लोधी अवयस्क था। किशोर सिंह लोधी उसके संरक्षक थे। उन्होंने दमोह जिले में क्रांति का मोर्चा थामा।

विजया पाठक

हिंडोरिया मध्यप्रदेश के दमोह शहर से 16 किलोमीटर दूर उत्तर-पूर्व की ओर बांदकपुर रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरठ-दिल्ली की क्रांति, झांसी का युद्ध, शाहगढ़ के राजा बखतबली के क्रांतिकारी प्रयासों की सूचना मिलते ही 42वीं देशी पैदल सेना के सैनिकों ने 1 जुलाई को सागर में क्रांति की तब उस क्रांति का असर दमोह में हुआ।

उस समय दमोह में अजीजुद्दीन डिप्टी मजिस्ट्रेट था। 4 जुलाई की सुबह क्रांतिकारी सागर से दमोह पहुंचे। दमोह में 31वीं, 42वीं तथा 52वीं देशी पल्टन की कई कंपनियां तैनात थीं। इनमें 42वीं पल्टन की दोनों कम्पनियों के सभी सैनिकों ने क्रांति का शंख फूंका। अंग्रेज सरकार को यह भी आशंका थी कि यदि 52वीं पल्टन की दोनों कम्पनियाँ 42वीं पल्टन की कम्पनियों में मिल जाती हैं तो दमोह को बचाना मुश्किल होगा इसलिए निर्णय लिया गया कि 42वीं पल्टन के सिपाहियों को निःशस्त्र कर दिया जावे, साथ ही 52वीं पल्टन की कम्पनियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाये। इसी कूटनीति के अंतर्गत दमोह को तथा खजाने को बचाया जा सकता है।

उस समय हिंडोरिया का जागीरदार उमराव सिंह लोधी अवयस्क था। किशोर सिंह लोधी उसके संरक्षक थे। उन्होंने

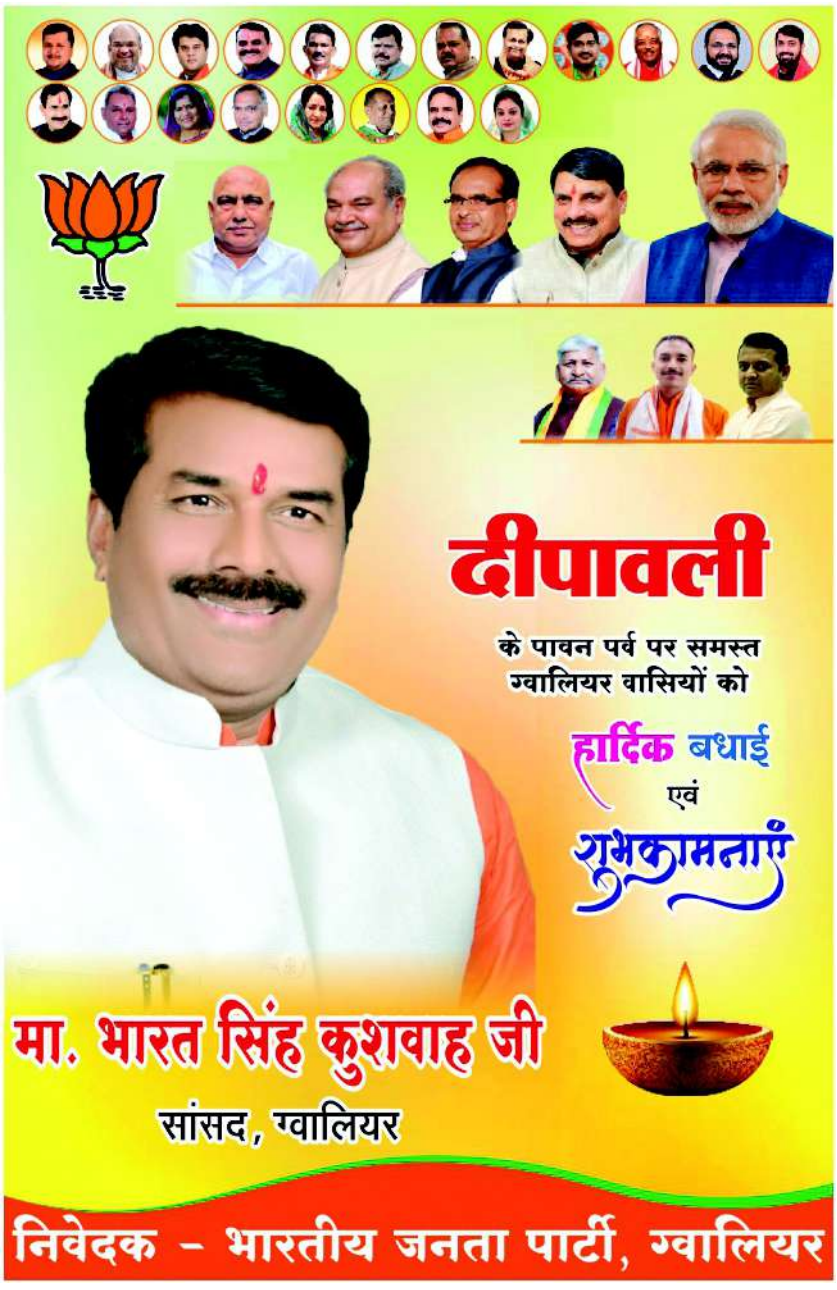


दमोह जिले में क्रांति का मोर्चा थामा। दमोह पर क्रांति का प्रभाव देख अंग्रेज अधिकारी सपरिवार 8 जुलाई को नरसिंहपुर आ गए। अंग्रेज अधिकारियों के भाग जाने के बाद तखत सिंह तहसीलदार, हजारीलाल थानेदार, रामप्रसाद फौजदारी सरस्तेदार, अकरम अली नायब फौजदारी सरस्तेदार डॉ. गिरीशचन्द्र तथा गुमास्ता खजान्वी भी अपने साथियों सहित क्रांतिकारियों से जा मिले।

क्रांतिकारियों का एक दल गढ़ाकोटा तथा रेहली की ओर दमोह के खजाने को प्राप्त करने के उद्देश्य से आ रहा था। वे सागर सेतोपें ला दमोह के दुर्ग को ध्वस्त कर वहाँ के खजाने को प्राप्त करना चाहते थे। इधर शाहगढ़ के राजा बखतबली ने हटा, बटियागढ़ तथा सिमरिया को भी जीत लिया और वहाँ अपने थाने स्थापित कर दिये।

दमोह खजाने को पाने में किशोरसिंह लोधी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। किशोरसिंह के साथ 52वीं देशी पल्टन के क्रांतिकारी सिपाही भी आ मिले। अब किशोरसिंह को और ताकत मिल गई। राजा शाहगढ़ तथा इन क्रांतिकारियों के सहयोग से किशोरसिंह 10 जुलाई को दमोह की ओर क्रांतिकारियों के साथ आगे बढ़े। नगर में पन्ना के राजा की सेना थी। उससे क्रांतिकारियों का मुकाबला हुआ। किशोरसिंह के दल ने पहले तो पन्ना राजा की सैनिक टुकड़ी को हराया। फिर वे जेल की ओर गये, क्रांतिकारियों ने जेल के कैदियों को मुक्त कर दिया। फिर वे दमोह शहर की ओर बढ़े। मुंसिफी तथा तहसील के अभिलेखों को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने अंग्रेजों की सरकारी इमारतों में आग लगा दी, अदालत को तोप से उड़ा दिया, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस को भी नष्ट कर दिया। किशोरसिंह ने दमोह में शाहगढ़ के राजा बखतबली के नाम पर थाना स्थापित किया तथा दमोह में तैनात अंग्रेजी सेना के भारतीय सिपाहियों को क्रांति से जुड़ने का अनुरोध किया। इसके बाद किशोर सिंह हिंडोरिया लौट गये।

अंग्रेज शाहगढ़ के राजा बखतबली, किशोरसिंह और उनके क्रांतिकारी सहयोगियों से आतंकित थे। 20 जुलाई 1857 के पत्र में कमिश्नर ने भारत सरकार को लिखा कि किशोर सिंह को



पकड़कर उसे तुरन्त दण्ड देना जरूरी है। तथा शाहगढ़ के राजा बखतबली को पकड़े जाने के बाद फांसी पर लटका देना चाहिए और उसके राज्य को जब्त कर लेना चाहिए।

अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी ने 21 जुलाई को हिंडोरिया के लिये प्रस्थान किया। किशोरसिंह के गाँव पर धावा बोला तथा गाँव को नष्ट कर दिया। तोपों से किशोरसिंह का महल पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। 28 जुलाई को सुबह शाहगढ़ के क्रांतिकारियों के तीन दस्तों ने, जिसमें एक हजार क्रांतिकारी थे, दमोह पर हमला बोल दिया। ब्रिटिश सेना ने क्रांतिकारियों से कड़ा मुकाबला किया। क्रांतिकारियों को पीछे हटना पड़ा और काफी क्षति उठानी पड़ी। उसी दिन राव स्वरूपसिंह, समानसिंह तथा सोनीसिंह बालकोट से अपने 200 साथियों को लेकर शाहगढ़ के राजा से आ मिले और उन्होंने दमोह पर आक्रमण कर दिया। उन्हें दमोह में तैनात 31वीं तथा 42वीं पैदल सेना ने पीछे खदेड़ दिया। ब्रिटिश सरकार ने राव स्वरूपसिंह, मानसिंह तथा सोनीसिंह की गिरफ्तारी के लिये क्रमशः 500 रुपये, 2150 रुपये और 25 रुपये पुरस्कार की घोषणा की। किशोरसिंह को जीवित या मृत गिरफ्तार करने के लिये ब्रिटिश शासन ने 1000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया।

किशोरसिंह से प्रेरित होकर दमोह के मालगुजार देवकरण ने भी क्रांति कर दी। उन्होंने दमोह के थानों पर कब्जा जमा लिया। स्थिति की विकटता को देखकर अंग्रेज अधिकारियों ने जबलपुर से सहायता मांगी। 24 अगस्त को नागपुर की सैनिक टुकड़ी दमोह पहुंची। शीघ्र ही अंग्रेजों ने बालकोट पर अधिकार कर लिया। एक छोटा किला नष्ट कर दिया गया। उसके बाद ठाकुर किशोरसिंह के हिंडोरिया स्थित किलाबंद मकान पर आक्रमण किया गया। सैकड़ों क्रांतिकारी अंग्रेजों द्वारा पकड़कर मौत के घाट उतार दिये गये। पन्ना के राजा के अधिकारी शअयामलेजू से अनुरोध किया गया कि वह दमोह जिले का प्रभार लें। श्यामलेजू ने 2 तोपों और सैनिकों को साथ लेकर दमोह में प्रवेश किया।

हालांकि दमोह पर अंग्रेजों की तरफ से पन्ना के श्यामलेजू का अधिकार था, पर हिंडोरिया और हटा के आसपास का क्षेत्र क्रांतिकारियों के अधिकार में ही बना रहा। 10 अगस्त, 1858 तक सागर-नर्मदा क्षेत्र के कमिश्नर मेजर एर्जकाइन ने दमोह जिले में शान्ति की घोषणा की। किशोरसिंह भावी क्रांति के लिये अज्ञातवास में चले गये।







पेट्रोल-डीजल के बढ़ते खर्च के बीच सरकार का बड़ा कदम!

नए यात्री वाहनों के लिए सीएएफई-3 नियम, ग्राहक की जेब और पर्यावरण पर असर?

किशन भावनानी

केंद्र सरकार ने यात्री वाहनों के लिए कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यानि सीएएफ़ई-3 के नए मानदंड अधिसूचित किए हैं। ये नियम 01 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक लागू रहेंगे और भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। इसका सीधा संबंध किसी एक यात्री वाहन के माइलेज से नहीं,बल्कि किसी वाहन निर्माता द्वारा एक वर्ष में बेची गई उसकी पूरी यात्री वाहन की औसत ईंधन खपत और उनसे होने वाले कार्बन उत्सर्जन से है।यानें सरकार किसी कंपनी से यह कह रही है कि वह केवल ज्यादा यात्री वाहन बेचने पर ध्यान न दे, बल्कि उसके पूरे वाहन समूह की औसत ईंधन दक्षता भी लगातार बेहतर हो।

सीएएफई -3 आखिर है क्या ?

यह वाहनों के लिए ईंधन बचत और प्रदूषण नियंत्रण का सामूहिक नियम है। किसी कंपनी की कुछ यात्री वाहन, कारें ज्यादा ईंधन खर्च करती हैं और कुछ कारें कम ईंधन खर्च करती हैं। सरकार प्रत्येक मॉडल को अलग-अलग एक ही सीमा में बांधने के बजाय कंपनी के पूरे वाहन समूह का औसत देखती है। इसीलिए इसे कॉरपोरेट औसत कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि समय के साथ कंपनियां ऐसे यात्री वाहन ऐसी कारें बनाएं जो समान दूरी तय करने में कम पेट्रोल या अन्य ईंधन खर्च करें और कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें। नए सीएएफ़ई-3 नियमों में यह व्यवस्था वर्ष-दर-वर्ष अधिक कड़ी होगी, ताकि वाहन उद्योग को अचानक नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से नई तकनीक अपनाने का अवसर मिले।

आम नागरिक के लिए बड़ा मतलब क्या है?

भविष्य की कारों यात्री वाहनों को अधिक ईंधन-कुशल बनाने का दबाव अब वाहन कंपनियों पर बढ़ेगा। नए ढांचे में संदर्भ स्तर पर ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया गया है। यह लगभग 16.7 प्रतिशत सुधार का लक्ष्य है। लेकिन



यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि ये आंकड़े किसी एक सामान्य कार के वास्तविक सड़क-माइलेज का दावा नहीं हैं। यह कंपनियों के पूरे वाहन समूह की नियामकीय औसत गणना का हिस्सा है।वास्तविक माइलेज कार के मॉडल, वजन, इंजन, सड़क, यातायात और ड्राइविंग शैली के अनुसार अलग हो सकता है।

क्या इसका मतलब है कि पेट्रोल-डीजल कारें यात्री वाहन बंद हो जाएंगी? इसको समझने की करें तो, नहीं। सीएएफ़ई-3 का अर्थ यह नहीं है कि 2027 से पेट्रोल या डीजल कारों की बिक्री बंद हो जाएगी। इसका उद्देश्य वाहन कंपनियों को अधिक ईंधन- कुशल और कम-उत्सर्जन वाले वाहनों की ओर ले जाना है। इसके लिए कंपनियों को केवल इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए बाध्य करने के बजाय कई तकनीकी रास्ते उपलब्ध कराए गए हैं।इनमें बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन, रेंज बढ़ाने वाली विद्युत तकनीक, प्लग-इन हाइब्रिड, मजबूत हाइब्रिड और फ्लेक्स-फ्यूल वाहन शामिल हैं। इस तरह सरकार ने एक ही तकनीक को अनिवार्य करने के बजाय अलग-अलग तकनीकों को अपनाने की सटीकता से गुंजाइश रखी है।

सुपर क्रेडिट को भी आसान भाषा में समझने की करें तो सीएएफ़ई-3 की चर्चा में सबसे ज्यादा तकनीकी शब्दों में से एक है

सुपर क्रेडिट। इसे सामान्य भाषा में कंपनियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन अंक समझा जा सकता है। यदि कोई कंपनी इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड या कुछ निर्धारित वैकल्पिक-ईंधन वाली कारें बेचती है, तो सीएएफ़ई की गणना में उन्हें सामान्य कारों की तुलना में अतिरिक्त लाभ मिलता है। इसका उद्देश्य कंपनियों को ऐसी स्वच्छ तकनीक वाले वाहनों का उत्पादन और बाजार में विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अंतिम अधिसूचित व्यवस्था में अलग-अलग स्वच्छ वाहन तकनीकों के लिए अलग-अलग गुणक रखे गए हैं। इसलिए इसे यह समझना अधिक सही होगा कि सरकार कंपनियों को स्वच्छ तकनीक अपनाने पर अनुपालन में अतिरिक्त सुविधा दे रही है, न कि ग्राहक को सीधे कोई नकद छूट दे रही है।

इथेनॉल, जैव ईंधन और सीबीजी को भी मिलेगा महत्व को समझने की करें तो नए ढांचे की एक महत्वपूर्ण विशेषता कम-कार्बन वाले ईंधनों को मान्यता देना है। इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल, जैव ईंधन और संपीड़ित जैव गैस जैसे विकल्पों को कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर के माध्यम से सीएएफ़ई-3 की गणना में मान्यता देने की व्यवस्था की गई है। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि सरकार केवल इलेक्ट्रिक वाहन को ही भविष्य का रास्ता नहीं मान रही, बल्कि भारत में उपलब्ध वैकल्पिक और अपेक्षाकृत कम-कार्बन ईंधनों को भी संक्रमण के हिस्से के रूप में देख रही है। इससे भारत के लिए पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल को बढ़ाने की दिशा में भी मदद मिल सकती है।

कार कंपनियां सिर्फ इंजन बदलकर ही लक्ष्य पूरा नहीं करेंगी। इसको समझने की करें तो, सीएएफ़ई-3 में ईंधन बचाने वाली विभिन्न तकनीकों को भी मान्यता दी गई है। इनमें बेहतर कांच, सूर्य की गर्मी को कम करने वाली तकनीक और अधिक दक्ष वातानुकूलन जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि भविष्य की कार में केवल इंजन या बैटरी ही महत्वपूर्ण नहीं होगी, कार की पूरी बनावट और उसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक भी ईंधन बचाने में भूमिका निभाएगी। सरकार ने मान्यता प्राप्त ईंधन-बचत तकनीकों की संख्या बढ़ाकर 12 की है और पात्र तकनीकों के माध्यम से उत्सर्जन गणना में निर्धारित लाभ दिया जा सकता है, जिसकी कुल सीमा 9 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति किलोमीटर तक है।

यात्री वाहनों, कार के वजन का भी नियम में महत्वपूर्ण स्थान है। इसको



समझने की करें तो, नए नियमों में कार के वजन को भी ध्यान में रखा गया है। हल्के और भारी वाहनों के लिए लक्ष्य एक जैसा नहीं रखा जाता, क्योंकि भारी वाहन को चलाने में सामान्यतः अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसी कारण सीएएफ़ई-3 में औसत वाहन वजन से जुड़ी गणना को नए तरीके से व्यवस्थित किया गया है। शुरुआती मसौदे में छोटे और हल्के वाहनों के लिए अलग रियायतों की चर्चा थी, लेकिन अंतिम व्यवस्था में छोटे पेट्रोल वाहनों के लिए प्रस्तावित विशेष छूट को बरकरार नहीं रखा गया। इसका अर्थ यह है कि केवल छोटी कार होने के आधार पर निर्माता को अलग से आसान रास्ता नहीं मिलेगा; उसे अपने पूरे वाहन समूह के औसत प्रदर्शन को सटीकता से सुधारना होगा।

साथियों बात अगर हम यदि कोई कंपनी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई तो क्या होगा? इसको समझने की करें तो सरकार ने इसके लिए भी लचीली व्यवस्था बनाई है। जो निर्माता निर्धारित लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करेगा, वह क्रेडिट अर्जित कर सकता है।वहीं किसी निर्माता की कमी होने पर वह उपलब्ध नियमों के अनुसार पिछले क्रेडिट का उपयोग कर सकता है, अन्य निर्माताओं के साथ क्रेडिट का लेन-देन कर सकता है या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक क्रेडिट खरीद सकता है।इसका उद्देश्य कंपनियों को एक झटके में दंडित करने के बजाय उन्हें तकनीकी बदलाव के लिए व्यावहारिक रास्ता देना है, जबकि लक्ष्य पूरा करने की जिम्मेदारी भी बनी रहेगी।

आम नागरिक को आखिर क्या फायदा होगा? इसको समझने की करें तो, इस पूरे नियम का अंतिम उद्देश्य केवल कार कंपनियों के आंकड़े सुधारना नहीं है।इसका असर लंबे समय में ईंधन खर्च, प्रदूषण, तेल आयात और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। यदि नई कारें औसतन कम ईंधन में समान दूरी तय करने लगती हैं, तो वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए ईंधन की खपत घटाने की संभावना बढ़ेगी।इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड विकल्पों की संख्या बढ़ने से उपभोक्ताओं के सामने तकनीक के अधिक विकल्प भी आ सकते हैं।साथ ही कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ शहरों और राजमार्गों पर परिवहन से होने वाले पर्यावरणीय दबाव को कम करने की दिशा में आगे बढ़ना है। हालांकि किसी व्यक्ति की वास्तविक बचत इस बात पर निर्भर करेगी कि वह कौन-सी कार खरीदता है, उसका ईंधन खर्च कितना है, वह कितनी दूरी चलाता है और वाहन की कीमत क्या है।



80 years after Independence, we, the manual scavengers, are still fighting for our freedom

Raj Valmiki

Even in 2026, when the practice of manual scavenging continues in India, how can we, the people forced into this work, claim that we are truly free? We remain trapped in the chains of a caste-based social order. This system has imposed, by birth, the degrading task of handling and carrying human excreta upon us.

Even today, the practice of manual scavenging continues in four states Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar and Jammu & Kashmir.

Dalit women continue to be engaged in the inhuman practice of removing human waste by hand from dry latrines. At the same time, men from the sanitation community are losing their lives from exposure to poisonous gases while cleaning sewers and septic tanks.

What a cruel irony it is that, on the one hand, India has made extraordinary advances in technology: Chandrayaan has reached the Moon and Mangalyaan has reached Mars. Yet, on the other hand, we have still failed to develop and implement safe technology for cleaning sewers and septic tanks.

The problem is not that we lack technological capability. Rather, it reflects the indifference of our governments and administration.



India continues to be deeply affected by caste discrimination, and administrative attitudes are also shaped by caste. The mindset of some officials appears to be that people born into communities traditionally engaged in sanitation are destined to clean filth and handle human waste that this is their hereditary occupation. If some of them die while doing this work, the officials don't seem overly concerned.

Caste discrimination and untouchability play a major role in the continuation of manual scavenging. Poor communities engaged in this work often face enormous barriers to education. Even while pursuing education, they may encounter untouchability and discrimination, which discourages and demoralises them. Similarly, when someone from the sanitation community attempts to start even a small self-employment venture, caste discrimination can become an obstacle. Their businesses may struggle because people from so-called upper castes refuse to join their clientele.



Article 17 of the Constitution abolished untouchability. Yet, because caste-based social practices continue to exert influence, untouchability remains present in everyday life in many forms.

Article 21 of the Constitution guarantees every citizen the right to life and personal liberty, which has been interpreted by the courts to include the right to live with dignity. Forcing a person to handle human excreta is a violation of that dignity. It is a violation of our basic human rights.

Eighty years after Independence, we remain shackled by the chains of manual scavenging, untouchability, caste-based oppression, servitude and patriarchy. India cannot truly free itself from the shameful practice of manual scavenging as long as there is even one person who is forced by their socioeconomic situation to handle another person's human excreta.

For almost half a century after Independence, dry latrines



remained part of India's sanitation system. Until 1993, local bodies and households continued to employ Dalit women and children to manually remove human excreta. This was a direct violation of the fundamental rights guaranteed by the Constitution.

It took India 46 years after Independence to enact its first law against manual scavenging. Two decades later, the country enacted *The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013*. Despite these legal measures, dry latrines, manual scavenging, and deaths in sewers and septic tanks remain a brutal reality.

After a nationwide survey conducted in 2024-25, the government announced that there was not a single district in the country with manual scavengers. Yet, as we celebrate 80 years of Independence, reports and accounts from Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar and Jammu & Kashmir indicate that Dalit women continue to clean dry latrines by hand.

These women, ignored by the system despite having to do manual scavenging and clean dry latrines for a living, are leading a democratic struggle for their dignity and rights.

We are fighting for: an India where no one is born into a particular occupation; where no one is forced to clean another person's excreta; where there are no dry latrines; and where no citizen is sent into a sewer or septic tank at the risk of losing their life.

India cannot be truly free as long as caste continues to determine who will clean our waste.



This cannot be the struggle of one community alone. It must become a struggle for all of us.

We, the Safai Karmachari Andolan (SKA), have launched a yearlong campaign to free India from the shameful practice of manual scavenging. There is a need for all who believe in the Constitution to come together and stand in solidarity.

The Safai Karmachari Andolan has resolved that by 15 August 2027, the country should be free from the practice of manual scavenging. This campaign is underway.

Manual scavenging exists because of caste. That is why Dr B. R. Ambedkar spoke of the annihilation of caste. Untouchability and patriarchy can be dismantled only when we confront the roots of caste itself.

The roots of caste and associated hierarchy are deeply embedded in the Hindu social order. Consequently, a religiously sanctioned hierarchy can become major obstacles to humanity, equality, liberty and fraternity. They stand in the way of Dalits living with dignity.

These barriers can be removed only when people place their faith not in the *Manusmriti* but in the Constitution of India.

Sadly, given the prevailing circumstances in the country, there are concerns about the protection of Constitutional values and the possibility of a return to a social order based on Manusmriti.

In such circumstances, those who believe in the Constitution and democracy need to remain more vigilant and alert than ever. Only then can practices as inhuman as manual scavenging be eradicated, and can Dalits live with the dignity that the Constitution guarantees them.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल



जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

बी.एस.सी. मास कम्यूनिकेशन (3 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671 संतोष गुप्ता - 9755618891

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य सुरक्षा का सुदृढ़ कवच



2.50 करोड़
से अधिक
आयुष्मान कार्ड

5.84 लाख
वय वंदना कार्ड जारी

1,672
शासकीय एवं निजी
अस्पतालों के नेटवर्क
के माध्यम से पात्र हितग्राहियों
को कैशलेस उपचार

स्वस्थ छत्तीसगढ़
सशक्त छत्तीसगढ़

हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें

सुशासन से समृद्धि की ओर



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

/ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

R.O. No. 13772/28



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

औद्योगिक विकास नीति 2024–30*

निवेश, नवाचार और रोजगार को नई गति

छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को
सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए

सिंगल विंडो सिस्टम 2.0:
एक क्लिक में सभी आवश्यक
अप्रूवल, **150** से अधिक सेवाएं

निवेशकों के लिए
एआई आधारित
'वाणी' प्रणाली

500 से अधिक
प्रशासनिक सुधार और
प्रक्रियाओं का सरलीकरण

'ईज ऑफ डूइंग
बिजनेस' को
सर्वोच्च प्राथमिकता



हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें

/ChhattisgarhCMO
/DPRChhattisgarh
www.dprcg.gov.in

R.O. No. 13772/28

सुशासन से समृद्धि की ओर